

संक्षिप्तवार्ता

बद्रीनाथ धाम में 2023 का टूटा रिकॉर्ड

चमेली। बद्रीनाथ धाम की तीर्थयात्रा ने इस साल एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 18.67 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या 2023 में बने 18.39 लाख भक्तों के पिछले रिकॉर्ड को पहले ही पार कर चुकी है। बद्रीनाथ धाम आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बीच, इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड टूट गया। तीर्थयात्रा में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए उम्मीद है कि इस साल भक्तों की संख्या 20 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी। अधिकारी और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 14,000 से ज्यादा भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री नाथ की पूजा-अर्चना की। तीर्थयात्रा को कड़ी निगरानी और तैयारी के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भक्तों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। रुद्रप्रयाग, चमेली और उत्तरकाशी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को चौबीसों घंटे अलर्ट है। ये जिले चार धाम यात्रा मार्ग से जुड़े अहम जिले हैं।

हीरा नगरी अब मेट्रो सिटी बनने की राह पर

सूरत। टेक्सटाइल और हीरा उद्योग के लिए दुनियाभर में पहचान रखने वाला सूरत अब आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। ब्रिज सिटी और सिल्क सिटी के नाम से मशहूर यह शहर अब मेट्रो रेल परियोजना के जरिए तेज, आधुनिक और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सूरत मेट्रो परियोजना में अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हार्दिकसित भारतरुद्र के सकलप और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में विकसित हो रहे आधुनिक बुनियादी ढांचे में सूरत मेट्रो परियोजना को महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। खास बात यह है कि मेट्रो के डिजाइन में भी सूरत की पहचान को प्रमुखता दी गई है।

मुंबई में उद्योग जगत से सीधा संवाद करेंगे सीएम

भोपाल। मध्यप्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों और औद्योगिक संभावनाओं को देश के प्रमुख उद्योग समूहों तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।

द सेंट रेंजिस, लोअर परेल में आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश में निवेश अवसरों पर संवादात्मक सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपतियों के साथ वन टू वन बैठकें करेंगे और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे।

अनोखे अंदाज और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ़ पीडीया

हर सड़क के साथ फुटपाथ जरूरी, पायलट प्रोजेक्ट के लिए पांच शहर चुनें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जिम्मेदार केंद्रीय अथॉरिटी की पहचान करने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश के पांच शहरों की पहचान कर वहां फुटपाथ से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सड़क के साथ पैदल चलने वालों के लिए उचित रूप से विद्युत और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ उपलब्ध कराना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए फुटपाथ की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।

मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को पीठ ने केंद्र सरकार से ऐसी केंद्रीय अथॉरिटी की पहचान करने को कहा, जो देशभर में फुटपाथों के निर्माण, उपलब्धता और रखरखाव की व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। अदालत ने जोर दिया कि केवल फुटपाथ



बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखना और नियमित रूप से उनकी देखरेख करना भी आवश्यक है।

अथॉरिटी के पास पर्याप्त

संसाधन होने चाहिए
केंद्र सरकार की ओर से पेश एंडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पीठ ने पूछा कि फुटपाथों की व्यवस्था सुनिश्चित करने

निर्माण के साथ रखरखाव पर भी जोर

अदालत ने संकेत दिया कि देशभर में फुटपाथों की व्यवस्था सुधारने के लिए एक प्रभावी और जवाबदेह तंत्र विकसित करना होगा। इसके तहत फुटपाथों का निर्माण, उनकी नियमित निगरानी, अतिक्रमण हटाने और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। पांच शहरों में प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट के जरिए फुटपाथों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की जा सकती है। इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय अथॉरिटी और आवश्यक संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार को अगली सुनवाई में जानकारी देनी होगी।

के लिए किस केंद्रीय अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अदालत ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी के पास पर्याप्त जमीन, वित्तीय संसाधन, कर्मचारी और जरूरी बुनियादी ढांचा होना चाहिए, ताकि वह देशभर में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। पीठ ने केंद्र से यह भी स्पष्ट करने को

कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन पांच शहरों का चयन किया जा सकता है। केएम नटराज ने अदालत को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने की बात कही। इसके बाद पीठ ने केंद्र को जिम्मेदार अथॉरिटी की पहचान करने और प्रस्तावित शहरों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की

अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 जून को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि निश्चित और विद्युत फुटपाथ पर पैदल चलना सविधान के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत के इस रुख का उद्देश्य पैदल यात्रियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को अक्सर सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अदालत ने फुटपाथों की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और उपयोगिता पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई।

बंगाल उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर हिरासत में

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में छह विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आम जनता उन्मयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस ने उनके पार्टी कार्यालय से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लेने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। वहीं, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों को जबरन उठाया जा रहा है। मतदान के बीच इन घटनाओं से बंगाल की चुनावी गतिविधियां चर्चा में आ गई हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटें, तमिलनाडु की मदुरैतकम और धारापुरम विधानसभा सीटें, पुडुचेरी की थ्रुनगावाडी विधानसभा सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह से मतदाता अपने मतधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे तक नंदीग्राम में 20.89 प्रतिशत और रेजीनगर में 18.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सभी सीटों के चुनाव परिणाम 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने विशेष अभियान चलाने के निर्देश

भोपाल। भारत सरकार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन में वृद्धि किए जाने के लिये देश भर में एक अभियान चला रही है। इसमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहाँ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी अधोसंरचना उपलब्ध है। इस संबंध में जरूरी कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर को दिये गये हैं।

नाइजीरिया में विमान हादसा, 32 की मौत की आशंका

अबुजा। नाइजीरिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। नाइजीरियाई वायुसेना का एटीआर-42 विमान दक्षिण-पश्चिमी ऑडो राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 32 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इनमें 25 यात्री और सात क्रू सदस्य शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। जानकारी के अनुसार विमान बेनिन सिटी से लागोस के लिए नियमित मिशन पर उड़ान भर रहा था। उड़ान के दौरान सोमवार सुबह करीब 8:13 जीएमटी पर एयर ट्रेफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया। इसके कुछ समय बाद विमान के ऑडो राज्य के इबोकोडा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। विमान का मलबा तटीय क्षेत्र के पास मिला।

हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। आसपास के इलाके में नावों की मदद से तलाशी अभियान



चलाया गया। दुर्घटनास्थल के पास स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। एक स्थानीय महिला ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज सुनी थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह बादलों की गरज है, लेकिन बाद

में विमान हादसे की जानकारी मिली। अधिकारियों के मुताबिक विमान किसी विशेष आपात स्थिति के लिए नहीं भेजा गया था और नियमित उड़ान पर था। हालांकि, दुर्घटना से पहले विमान में क्या

तकनीकी समस्या आई या हादसा किस वजह से हुआ, इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू की जा रही है।
नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना की तत्काल और पूरी जांच के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति ने हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय करने पर भी जोर दिया। यह हादसा नाइजीरिया में हाल के वर्षों में हुए गंभीर सैन्य विमान हादसों में शामिल हो गया है। मई 2021 में सेना के शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अताहिरु समेत 11 लोगों की विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। अगस्त 2015 में भी एक सैन्य विमान हादसे में सात लोगों की जान गई थी।

असम में गार्डरेल से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की मौत और 3 घायल

दिसपुर। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में मंगलवार को नेशनल हाईवे 27 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गुवाहाटी से गुणांव जा रही एक तेज रफ्तार कार खेतड़ी इलाके में हाईवे की गार्डरेल यानी सुरक्षा रेलिंग से जा टकराई। पुलिस के अनुसार, इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान मनिमा बेगम (40), रिबुल अली (17) और अमीरउद्दीन (40) के रूप में हुई है।



संबोधित कर दिपके ने बताया कि चंद्रपुर पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल न होने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के दिल्ली यात्रा खर्च के स्रोत के बारे में भी पूछताछ की। दिपके ने महाराष्ट्र पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ

लक्षद्वीप: पीएम मोदी की यात्रा से सामरिक कायापलट तक



नई दिल्ली। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें वायरल होने के बाद बॉयंगटोल मालदीव और एक्सलोर लक्षद्वीप की बहस छिड़ी थी। इन दो सालों में, कोच्चि से 220-440 किलोमीटर दूर स्थित 36 द्वीपों के समूह में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सामरिक मौजूदगी के लिहाज से बड़ा बदलाव आया है। कुल 32 वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में केवल 10 द्वीप आबाद हैं। दशकों तक लक्षद्वीप तक पहुंच चुनीतीपूर्ण थी, अगली में केवल एक छोटा एयरस्ट्रिप था। पीएम मोदी की यात्रा ने लक्षद्वीप राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से ला दिया, जिससे पर्यटकों की संख्या तीन गुना बढ़ी है। नए बीच रिसॉर्ट्स, होमस्टे और बेहतर हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी की योजनाएं आकार ले रही हैं। केंद्र सरकार दोहरा उपयोग वाले बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है। अगली एयरफील्ड के विस्तार और मिनिर्कोय में नौसेना बेस के साथ नया सैन्य-सिविल एयरफील्ड विकसित हो रहा है।
2023 तक लक्षद्वीप में नौसेना की उपस्थिति सीमित थी। पीएम मोदी की यात्रा के दो महीने बाद, 6 मार्च 2024 को, मिनिर्कोय में आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया, जिसने पुराने नौसैनिक डिपेंडेंट को एक पूर्ण इकाई में बदल दिया। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिर्कोय, महत्वपूर्ण आट और नौ डिग्री चैनलों के पास स्थित है। आईएनएस जटायु समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी में अहम भूमिका निभा रहा है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप बिटरा अब एक तीसरे नौसैनिक ठिकाने का केंद्र बनने की तैयारी में है। यहां नौसेना का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट चल रहा है। इसका उद्देश्य उत्तरी लक्षद्वीप में निगरानी बढ़ाना और नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच को विस्तार देना है। स्थानीय निवासियों में उम्मीद के साथ विस्थापन की चिंता भी है। अधिकारियों के मुताबिक, बदलाव के पीछे केवल पर्यटन नहीं, बल्कि सुरक्षा भी एक बड़ी वजह है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी रिसर्व जहाजों की मौजूदगी और समुद्री डकैती की घटनाओं के बीच लक्षद्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।

लोकसभा चुनाव-2029 की बहस के बीच टीवीके इंडिया गठबंधन में शामिल!

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी, तमिलनागा वेत्री कडगगम (टीवीके), औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश में लोकसभा चुनाव 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर गहन बहस जारी है। हालांकि, संसद में फिलहाल टीवीके का कोई

प्रतिनिधित्व न होने के कारण, इस गठबंधन का प्रभाव दिल्ली तक अभी सीमित है। कांग्रेस के तमिलनाडु प्रमुख बी मणिक्म टेगोर ने टीवीके के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में विपक्षी मोर्चा और अधिक मजबूत होगा, जिससे आरएसएस-भाजपा सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक मुकामला और प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकेगा।

विजय के इस निर्णय को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह



की अटकलें हैं। एक पहलू इसे देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में

टीवीके सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था, लेकिन उसे केवल 108 सीटें ही मिली थीं। सरकार बनाने के लिए उसे कम से कम 10 और सीटों की आवश्यकता थी। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने टीवीके का साथ दिया, और वीसीके व आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से पार्टी राज्य की सत्ता तक पहुंच पाई। वहीं, इस फैसले को रणनीतिक आवश्यकता के रूप में भी देखा जा रहा है। पहली बात तो यह कि जिस गठबंधन के साथ टीवीके राज्य में सरकार चला रहा है, गठबंधन का ढांचा भी काफी हद तक वैसा ही है।

दूसरा, यह कदम टीवीके को लोकसभा चुनाव 2029 में सीटों की मजबूत दावेदारी पेश करने का अवसर देगा, जिससे उसे राष्ट्रीय

स्तर पर किसी नए गठबंधन की तलाश या गठन से मुक्ति मिलेगी। शनिवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस, टीवीके,

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल के शीर्ष नेता शामिल हुए।

कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी

टीवीके का प्रतिनिधित्व अध्व अर्जुन और मारी विल्सन ने किया। टीवीके पहले मजबूती से सी जोसेफ विजय को प्रधानमंत्री पद के अगले चेहरे के तौर पर पेश कर रही थी, जिसके चलते कांग्रेस के साथ उसकी तीखी बयानबाजी भी हुई थी। अर्जुन ने कहा था, मैं आज साफ तौर पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री दक्षिण से ही आना चाहिए और दक्षिण से ही प्रधानमंत्री बनेगा, हो सकता है अभी नहीं। भविष्य में वह हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करेगा और हर भारतीय के साथ समान व्यवहार करेगा। अब गठबंधन में शामिल होने के बाद विजय को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो सकती है। हालांकि ही में ऐसी खबरें भी आई थीं कि द्रविड़ मुन्नेत्र कडगगम सांसद कनिमोई कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

संपादकीय

**ताकि सारे
बयान दर्ज हों**

सरकार आम लोगों की कैसे हो सकती है, इसका एक परिचय यही है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कुछ ऐसे स्थानों में प्रवास किया,

माहौल का मुआयना, माहौल पर पकड़ और माहौल की निरंतरता में हिमाचल सरकार के कदम जिस तरह गांव के द्वार पर पहुंच रहे हैं, उसका मूल्यांकन जरूरी है। रामपुर बुधशहर के गांव काशपाटन में सरकार का पहुंचना, सरकार का होना है।

बीच जवाबदेह समाज के खंडहर पैदा कर रहा है या ऐसे मॉडल चुन रहा है, जहां निगरानी की जरूरत है।

ऐसे में प्रदेश के प्रशासनिक व प्रमुख शहरों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर मार्निंग वाक के आयोजन हों, तो मालूम होगा कि हमारे स्थानीय निकायों और मानवीय अपेक्षाओं के बीच कितना अंतर है। प्रदेश की स्वच्छता का वृतांत अगर मिल सकेगा है, तो इसे शहरी इलाकों में खोजना होगा। शहरों में सुबह की सैर का सामना कूड़े के ढेर, रेस्तरां के बाहर बिखरे सामान, सड़कों पर शराब की बोतलें, आवारा पशु और बंदरों की टोलियों से होता है तो ट्रैफिक के निरंकुश इरादे और कहीं बाजारों के बरामदे में बैठी उदास धुन, बहुत बुरा चक्र कहती है। बेशक गाहे गाहे वनमंजु वनमंजुशी शिल्पता के केंद्रों के बहाने शहर और शहर के बाशिंदों के कई सवाल चुटकियों में हल कर देते हैं, लेकिन जरूरत है एक चक्कर बीबीएन की आर्थिक छत के नीचे लगाया जाए। पर्यटक शहरों की अव्यवस्थाओं को जानंचे कि लिए मार्निंग वाक किया जाए। महत्समा गांधी जयंती के दिन संसदे में अधिक सफाई वहां हुई, जहां से प्रशासन ने प्रांभत फरियां लगाईं, तो यह जरूरत हर दिन की है। इन पंक्तियों के लेखक से गांधी जयंती के दिन सुबह-सुबरे एक पर्यटक पूछता है कि शौचालय कहाँ है, तो शहरी विकास की सारी खिड़कियां टूटी हुई दिखाई देती हैं। धर्मशाला शहर के कचहरी से बार मेमोरियल तक अगर पर्यटकों के लिए शौचालय मुहैया नहीं कराव सके, तो सारे प्रदेश की सड़कों पर हम क्या उम्मीद रखेंगे।

भल हा ग्रामाण आर्थिकां के जेत जपना का प्रस्ताहन जरुआ ह
या प्रकृति के संदेश प्रदेश में अतिम नागरिक तक पहुंचने चाहेए,
एलेक्जिन्डर हिमालय के भीतर कई हिमाचल आज भी उपेक्षित हैं, तो
इसकी खबर भी लेनी होगी। इस बार सप्ताहांत की लंबी छुट्टियाँ ने
हिमालय के सारे संदूक पर्यटन से भर दिए, जो तो रास्ते अटल
हमाल, मनाली, मकलोजंगर, डलहौजी, बीड़-बिलिंग, शिमला या
कसौली को निकले, उनकी हालत का बयान दंत होना चाहिए।
हिमालय की सोहबत में हिमाचल की सुरत बिगड़ती है, तो जानना
होगा कि क्यों हर पर्यटक स्थल को ट्रैफिक जाम से कितनी रगड़
लगाती है। भारी संख्या में सैलानियों के आने से कई शहरों में कचरा
मुह्रासे निकल जाते हैं। गांव में आर्थिकां की नजरिया परंपराओं को
जीवित रखता है, तो शहर में बढ़ती रौनक व्यवसाय है या रोजगार
है। ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री हिमाचल के कठिन इलाकों में प्रयास
कर रहे हैं, उन्हें शहर व पर्यटक स्थलों को कठिनाता के बीच मार्गिन
करती की श्रृंखला भी शुरू करनी चाहिए।

12 और 13 सितंबर 2026 को हुए बिबिस शिखर सम्मेलन के बाद, संयुक्त घोषणापत्र से जुड़े असली मुद्दों— यानी उठाए गए, सुलझाए गए या नजरअंदाज किए गए मुद्दों— पर बात करने के बजाय, विषय ने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चुना जो असल में कोई मुद्दा ही नहीं है। बिबिस से जुड़े शाकाहारी खाद्य वस्तु परीक्षा शायद ही ज्ञात विषय बिबिस के एजेंडे पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें सरकार को फायदा मिल सकता है। सरकार अलग-अलग रास्ते रखने वाले पक्षों को कई अलग मुद्दों पर एक साथ लाने में कामयाब रही है, जैसे कि मुक्त और निष्पक्ष व्यापार, घरेलू मुद्राओं में व्यापार, और ग्लोबल वैल्यू चेन व जरूरी खनिजों को इथियोपिया की तरह इस्तेमाल पर रोक। साथ ही, संयुक्त घोषणा पत्र में नागरिक और परमाणु प्रविष्टियों पर हमला करने वालों और व्यापारिक रास्तों को रोकने वालों की निंदा भी की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का तर्क है कि सरकार एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है जो शाकाहार को पसंद करने के लिए है, और इस प्रक्रिया में वे उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो मांसाहार हैं। शायद वे नरेंद्र मोदी के झूठ कदम के लिए आरएसएस की ओर झुका रह रहे हैं। हालांकि, ईश अलवास के सहयोगी भी इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं हैं, लेकिन किसी तरह कांग्रेस को लगता है कि उन्हें मांसाहारियों का समर्थन मिलेगा, जो उनके अनुसार आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं। हालांकि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन यह विवाद हमें शाकाहार बनाम मांसाहार के मुद्दे पर चर्चा करने का मौका देता है। स्पष्ट करना होगा कि यह लेख मांसाहार का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए शाकाहार के महत्व को उजागर करने के लिए लिखा गया है।

होलोक रस्तुल गांधी का दाला है कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसहारी हैं, लेकिन संसद ज्यादा हवाला दिया जाना चाहिए यू एसिसर्व नहीं (2001) कहता है कि लगभग 39 प्रतिशत भारतीय इसका न किसी रूप में मांस नहीं खाते हैं । यानी संसद में 39 प्रतिशत लोगों ने खुद को शाकाहारी बताया। ज्यादातर भारतीय कभी-कभी मांस खाते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति मांस को खपत 3.1 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जबकि अमरीका में यह 109 किलोग्राम, यूरोप में 84 किलोग्राम और दुनिया भर में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 44.5 किलोग्राम है। जबकि भारत की 39 प्रतिशत आबादी पूरी तरह शाकाहारी है, दूसरे देशों में मुश्किल से 3 से 5 प्रतिशत आबादी ही शाकाहारी है। भारत में दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत शाकाहारी आबादी रहती है और यहां के लोगों का औसत मांस का सेवन अमरीका के मुकाबले बहुत कम (सिर्फ 2.8 प्रतिशत) है, यही बात भारत में शाकाहार के इतने बड़े पैमाने पर होने की वजह बनती है। असल में, कई भारतीय शाकाहारी होने के बावजूद धार्मिक मान्यताओं के कारण कुछ खास तरह का मांस नहीं खाते । उदाहरण के लिए, हिंदू और सिख बीफ (गोमांस) नहीं खाते, जैन धर्म में किसी भी तरह का मांस खाना मना है, और

The logo for BRICS India 2026. It features a stylized flame or flower-like shape composed of five segments in blue, yellow, orange, green, and red. Below this graphic, the word "BRICS" is written in large, bold, multi-colored capital letters (B: blue, R: red, I: yellow, C: green, S: orange). Underneath "BRICS", the words "INDIA 2026" are written in a smaller, orange, sans-serif font.

मुसलमान भुखार का मांस नहीं खाते। हालांकि के दिनों में शाकाहार के अंदर ही एक नया चलन बढ़ा है, जिसे हवीगन मूवमेंट कहा जाता है। इसमें मांस के अलावा दूध और दूध से बनी चीजों जैसे जामवंरों से मिलने वाले अथवा उत्पादों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। उनका तर्क है कि दूध के उत्पादन में जानवरों के साथ दूरदा हो रही है। माना जा है कि दुनिया की 1 से 2 प्रतिशत आबादी ने वीगन खानपान अपना लिया है। हालांकि, वीगन जीव-प्रेमीता का काफी विरोध भी होता है, विरोध करने वालों का तर्क है कि दूध (जिसे शाकाहारी माना जाता है) का सेवन न करने से पशुपालन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के मौकों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह समझना जरूरी है कि दूध का उत्पादन और डेयरी उत्पादों का सेवन हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है।

शाकाहार और जलवायु पारवर्तन

जैसे इसनागलेबत पुर्वी के बहने तापमान के ऊँची में एक बड़ सट्ट के सामना कर रही है, जिसे हमग्लोबल वार्मिंग कहें सक्त जात है। औद्योगीकरण के शुरूआत के बाद से पुर्वी का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और आबादी पाँच गुना बढ़ गई है। यह सच है कि ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से औद्योगीकरण का नतीजा है, लेकिन एक तरफ खाने-पानी के वीजों का ज्यादा उत्पादन और दूसरी तरफ खाने की बर्बादी ने भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी योगदान दिया है, जिससे आधिकारिक ग्लोबल वार्मिंग को रूढ़ी है। फीडपीजी बढ़ने के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और इसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की ज़िज़्दी खर्चों और खाने की बर्बादी भी बढ़ गई है। शाकाहार बनाम माँसाहार की बहस में, आंकड़ों को समझना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया की 71 प्रतिशत आबादी जमीन पानी से ढकी है, जबकि सिर्फ 29 प्रतिशत जमीन है। इस 29 प्रतिशत में से सिर्फ 20%

प्रतिशत रहने लायक है, 10 प्रतिशत खेती के काम आती है, और खेती लायक जमीन में से सिर्फ 2.4 प्रतिशत पर फसल उगाई जाती है और 8 प्रतिशत का इस्तेमाल पशुपालन के लिए होता है। जमीन का यह 2.4 प्रतिशत हिस्सा इनसानों की 83 प्रतिशत कैलोरी और 63 प्रतिशत प्रोटीन की जरूरतें पूरी करता है, जबकि पशुपालन में इस्तेमाल होने वाली लगभग 77 प्रतिशत खेती की जमीन इनसानों की कैलोरी की 15 प्रतिशत और प्रोटीन की 37 प्रतिशत जरूरतें ही पूरी करती है। भारत के पास दुनिया की जमीन का सिर्फ 2 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि हमारी आबादी दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत है। भारत में दुनिया के 30 प्रतिशत पशुधन और 8 प्रतिशत जैव-संसाधन हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन पैदा करने के साथ-साथ, भारत अपने जैव-संसाधनों को बचाने में भी सफल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, और जो लोग मांस खाते भी हैं, उसमें से ज्यादातर कभी-कभी ही ऐसा करता है। भारत में पशुपालन दुनिया की मांसाहारी आबादी की जरूरतें भी पूरी करता है।

छाया देन वाली बात हो गई भारते हर साल 13 अलायन्स मोटोक्रेन भरे को मांस नयात करते हैं, इसके अलावा लगभग 50 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के अन्य खाद्य उत्पाद भी निर्यात करती हैं, और इस तरह भारत अमरीकी शाकाहारी आदते दुनिया में भोजन की कमी को रोकती हैं । अगर हम दुनिया की शाकाहारी आबादी पर नजर डालें, तो कुल शाकाहारी आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत में रहता है । दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में, मांस की खपत के लिए जरूरी पशुपालन से होने वाला उत्सर्जन लगभग 15 प्रतिशत है । आंस, दाल या सब्जियों के उत्पादन की तुलना में एक किलोग्राम मांस के उत्पादन से 20 से 30 गुना ज्यादा ग्रीनहाउस गैस निकलती है । यह समझना आसान है कि अगर दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी भी शाकाहारी बन जाए, तो भोजन से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 30 से 35 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है । मांस के उत्पादन से बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, जबकि डेयरी से ग्रीनहाउस गैस का सिर्फ 3-4 प्रतिशत हिस्सा ही निकलता है । इसमें से आधा हिस्सा उत्सर्जन से आता है और बाकी हिस्सा फीड, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और फूट पैक मैन्युफैक्चरिंग से आता है । यह समझना जरूरी है कि जहां एक किलो मांस के उत्पादन से 60 किलो ग्रीनहाउस गैस (मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड) निकलती हैं, वहीं एक लीटर दूध से सिर्फ 3-2 किलो ग्रीनहाउस गैस निकलती हैं । अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की मुश्किलें से बचाना हो तो शाकाहारी को तेजी से बढ़ावा देना होगा । हमें ग्लोबल वार्मिंग से कुछ राहत मिल सकती है । हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को शाकाहारी आदत बनाना चाहते हों ।

डा. अश्वना महाजन, पूर्व प्राफ़िसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

क्या भारत बांग्लादेश के रास्ते पर चल पड़ा?

बांग्लादेश और भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं, फिर भी दोनों देशों की घटनाओं से हम मूलतः पूर्ण समानता दिखाई देती हैं। जब जनता को एक महापुरुष होने लगे, चुनावी व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाएँ निष्पक्ष नहीं रहीं, चुनावी संवैधानिक संस्थाएँ सरकार के दबाव में काम करती हुईं-जनत आ रहीं हैं, तब अंतोष केवल राजनीति के दबाव को तभी सीमित नहीं रहता। जब यह अंतोष सत्ता केवल नृपवृत्तों है, उसके बाद स्थिति गंभीर होती जाती जाती है। बांग्लादेश में जनवरी 2024 के चुनाव में प्रमुख विपक्षी लक्ष्मी जैती सरकार के गठन का माध्यम बना। प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। सरकार पर विश्वास को खाने तथा चुनाव को बहिष्कार करने के आदेश लगे थे। [न्याय के बाद भी अंतोष समाप्त नहीं हुआ। शोध हसीना की तानाशाही और भी बढ़ रही है।] जनवरी 2024 में सरकार की नीतियों में आराक्षण के मुद्दे शुरू हुआ, [अब्रु आंदोलन वीर-धीरे सरकार-विरोधी आंदोलन में बदल गया।] [युवाओं की भीड़ सड़कों पर आई।] पुलिस और सुरक्षाबलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अंततः संसद प्रमुख विपक्षी वलार-उर-जमाना ने शोध हसीना सरकार के संस्थेन में आंदोलन को बहुरूपीकरण को सेना ने इनकार कर दिया। 15 अगस्त 2024 को हसीना ने भारत में शरण ले ली। इस कारण भारत और बांग्लादेश के संबंध भी खराब हुए। [यहाँ से भारत के लिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संकट निकलता है। सरकार केवल चुनाव लड़कर मजबूत नहीं होती है। सरकार की वास्तविक ताकत जनता के विश्वास में निहित है।]

[illegible]

आम हूँ। उसके
आम है। आम
रोप है, प्रिचिया में
जिनने के लिए
वो चुनावों को
न 13 करोड़ नाम
उस परी कर चुके
हैं। पात्र नगरिकों
को प्रिचिया

गडबडी को लाने, मतदाता सुनने में देखे हुए है। चुनावों
को सफलता पर सहज हो रही है। बलिक रचना में
जांच, ग्राहिक समीक्षा और पारदर्शी प्रिचिया से विषयों को
मिन्ना जाहिर। चुनाव आयोग को विषय के साथ साबित करना
पारिषद। विषय और आम जनता को भी विश्वास में लेना चाहिए था।
न्यायपालिका को भी अपनी भूमिका आम करनी थी, लेकिन पिछले
दो-दस वर्षों से सब अपनी अपनी प्रिचिया से नजर है। यदि चुनाव
आयोग पर आरोप करते हैं, तो आयोग को आंकड़े, प्रिचिया और
नियम सारजनिक करके जनता का विश्वास जताना चाहिए। यदि

भारत में आमों
संपत्तिका या संपत्ति
है। उसे विश्वास
बालादिरिचिया में
केवल मतदान को
चाहिए, आम
सुरक्षित है। उस
निष्कर्ष है। चुनाव
आयोगपालिका

है, तो उसे सुधारना नृणा आदि पत्नी से कोलंकर की मजदूरी नृणा आदि पत्नी से हिरसो से नृणा आंगांग और मूछा नृणा को खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 12 अद्वय को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। उदय कान्कर और राजा ठाकरे ने नृणा आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शन की भीमका कोलंकर भी भीड़ सड़कों को बंद कर बीस वार्मान आंदोलन को देखते हुए है। बंगालदेश में आंदोलन सतत चले रहते हैं। सैन्य इस्तीफे की स्थिति तक पहुंच गया है। भारत में सैन्य, आर्थिक, राज्यों की संरचना में संसद, भीड़स्थ स्वतंत्र मीडिया के रूप में मौजूद है। कोलंकर स्थित नृणाओं की भीमका से स्थितियों को नृणाओं की मूछाओं की अति महत्वपूर्ण के रूप में आना होगा।

नहीं है। मतदाता को यह विचारसौ होना चाहिए कि मैंने जिस पार्टी का चुनाव किया है वह मुझे किस प्रकार की सरकार देगी? उस सरकार के उद्देश्य और नीतियों से क्या प्रभावित होकर वह कार्य करेगा? इसका जवाब देना ही मतदाता का अधिकार है। मतदाता को यह भी सोचना चाहिए कि मैंने किस पार्टी का चुनाव किया है वह मुझे किस प्रकार की सरकार देगी? उस सरकार के उद्देश्य और नीतियों से क्या प्रभावित होकर वह कार्य करेगा? इसका जवाब देना ही मतदाता का अधिकार है। मतदाता को यह भी सोचना चाहिए कि मैंने किस पार्टी का चुनाव किया है वह मुझे किस प्रकार की सरकार देगी? उस सरकार के उद्देश्य और नीतियों से क्या प्रभावित होकर वह कार्य करेगा? इसका जवाब देना ही मतदाता का अधिकार है।

(लेखक - समेत जैन)

(लेखक- सनत जैन)

सूचना कांति के इस युग में दुनिया हमारी हथेली पर सिमट गई है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने संचार के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। कभी समाचारों के लिए लोगों को अगले दिन का अखबार, रेडियो का निधार्ति बुलेटिन या टेलीविजन के समाचार कार्यक्रमों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घन्टाघट घंटने के कुछ ही क्षणों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं।

सूचना का यह तीव्र प्रवाह लोकतंत्र के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इसी डिजिटल क्रांति ने एक नए क्रांति का जन्म दिया है, जिसे आज समीक्षी मीडिया पत्रपुस्तकें एक नया नाम दे रही हैं। पत्रपुस्तकें समाज का हिस्सा हैं और उनमें से अनेक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, उम्मीदों और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सहानी की कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रभावों को पहचान दिखाई है, छोटे-छोटे व्यापारियों को बाजार में प्रविष्ट कर दिया है और दूसरों को सामंजस्यपूर्ण विकास को विश्व पटल तक पहुंचाया है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी है, जहां बिना स्थिति के जांचे, बिना किसी संपादकीय जांच की जा रही है। यही स्थिति नितांत अस्वास्थ्यकर है। आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्वयं को पत्रकार, शिक्षण या विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन उनके पास न पत्रकारिता की प्रशिक्षण होता है, न समाचार लेखन की समझ और न ही मीडिया की नैतिक मर्यादों का ज्ञान। परिणामस्वरूप अप्रुप सूचनाएं, आधे-अधूरे तथ्य, भ्रामक शीर्षक

और ससनीबीज वीडियो कुछ ही मिमटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। इससे अप्रवाही का बाजार गर्म होता है और समाज में भ्रम तथा अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं से प्रकाशिता और ब्लॉगिंग आधार ब्लॉगिंग के बीच अंतर को समझना आवश्यक हो जाता है। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग मुख्यतः व्यक्तिगत विचार, अनुभव, जानकारी या मनोरंजन प्रस्तुत करने का माध्यम हैं। इनमें रचनात्मक स्वतंत्रता अधिक होती है। दूसरी ओर प्रकाशिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सत्यता, संतुलित, निष्पक्ष और जर्नलिस्टिक सूचना समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। प्रकाशिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहती है क्योंकि उसका उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना, समाज की आकाश बनना और सत्य को तथ्यों के आधार पर सामने लाना होता है। प्रकाश बनने के लिए केवल कैमरा या मोबाइल फोन पर्याप्त नहीं होता। प्रकाशिता एक विषय है, जिसका अपना इतिहास, संदर्भ, आधार सहित, भाषा, कानूनी दायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रकाशिता के विद्यार्थी वर्षों तक समाचार लेखन, संपादन, मीडिया कानून, प्रेस

[illegible]

पार, डिजिटल पोर्टल, यूट्यूब केवल
उपेन्द्र इसका प्रमाण हैं। और केवल
प्रक्रिया अपनाते हैं, जबकि व्यक्तिगत
रार यह प्रक्रिया प्रायः अनुपस्थित रहती
कहा देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
व्यक्ति भी जोड़ा है, लेकिन भी व्यक्ति की
राष्ट्रीय सुरक्षा या न्यायिक प्रक्रिया
प्रमुख जानकारी साझा करना केवल
थालीयों में कानूनी प्रश्न भी बन सकता
संस्थानों का बढ़ना स्वाभाविक
सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में
स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है। एक
लोकगायक, हस्तशिल्पी, बुनकर,
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के
को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान
दिला रहे हैं। किन्नरी शैल, कुल्लू की टोपी, चंबा स्माल,
सिरमौर और शिमला की पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य,
डिजलसीत, मेले, देव परंपराएं और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को
डिजिटल माध्यम से नई पहचान मिली है। यह स्थानीय मीडिया
का सकारात्मक पक्ष है। दूसरी ओर, रील्स और शॉर्ट वीडियो
की संस्कृति ने जीवनशैली और सामाजिक व्यवहार को भी
प्रभावित किया है। आज अनेक युवा कैमरे के सामने लोकप्रिय
होने की हांड में अपनी भाषा, पहनावे और व्यवहार को कुटुंब
रूप से बदल रहे हैं। हैलो गाइड, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
करना मात्र भूलना, जैसे वाक्य आज एक नई डिजिटल संस्कृति
का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, यदि सामग्री
ज्ञानवर्धक, रचनात्मक या मनोरंजक हो, लेकिन पर्यटन
उत्पन्न होती है जब लोकप्रियता के लिए अश्लीलता, अभद्र भाषा,
खतरनाक स्टंट, निजी जीवन का अनावश्यक प्रदर्शन या
सामाजिक मूल्यों की अनेकदेशी की जाने लगे। इसलिए पथ,
भाषा, संतुलन और नैतिकता सर्वोपरि होने चाहिए।

उमा ठाकुर, स्वतंत्र लेखिका

आलेख

कोई भी देश या समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह अन्दरूनी तौर पर मजबूत न हो। एक मजबूत समाज वह नहीं होता जो बाह्य मतभेद मौजूद न हो, बल्कि वह होता है जहाँ मतभेदों को समझदारी, आपसी सम्मान और साझा इलाक़ी की भावना के साथ संभाला जाय। भारत हमेशा से अलग-अलग धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का पावन घर रहा है। यही विविधता इसकी ताकत बनी क्योंकि यही दीवार दर पीढ़ी भारतियों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए मिल-जुलकर रहने का हुनर सीखा है। तेज संघर्ष और सोशल मीडिया के इस दौर में विभाजनकारी प्रवृत्तियों के मुकाबले एक सामाजिक स्थिरता को मजबूत बनाना हमें नागरिक, समाजिक नेता, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) के साथी सी ज़िम्मेदारी है।

बड़े मतभेदों से नहीं बल्कि आपसी विश्वास में धीरे-धीरे आने वाली कमी से होती है। गलतफहमियाँ, अफवाहें, एकतरफा जानकारी और भावनाओं पर आधारित बातें अगर समझ रहे न रोकी जाएँ तो सामाजिक दूरियाँ बढ़ सकती हैं। वे समाज जो नियमित मेलजोल, खुली बातचीत और आपसी समझ-बुझ के

बढ़ावा देते हैं, वे ऐसी प्रवृत्तियों का बेहतर तरीका से मुकाबला कर सकते हैं। मतभेद पैदा होने से पहले मजबूत रिश्ते कायम करना सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने का एक असरदार उपाय जरिया है।

विचारों के अंतर को शांतिपूर्ण ढंग से संभालना एक परिपक्व और जिम्मेदार समाज की पहचान है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था और हर समाज में अलग-अलग राय का होना स्वाभाविक बात है। जरूरी नहीं कि ये मतभेद दुश्मनी में बदलें। सामान्यतः बातचीत को लोगों को अपने विचार रखने, गतकथनियों को दुरु कर देने और अपनी पहचान या मान्यताओं से समझौता किए बिना साझा बिंदु तलाशने का अवसर देती है। धैर्य से सुनना, शालीनता से बात करना और मतभेद रखने वालों के आत्मसम्मान की कद्र करना ऐसा माहौल बनाता है जहां मतभेद सामाजिक एकता को कमजोर करने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं।

धार्मिक और सामाजिक नेताओं की भूमिका सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा में बेहद अहम है। उनका प्रभाव सिर्फ इबादतगहों (पूजा स्थलों) तक सीमित नहीं है बल्कि परिवारों और मोहल्लों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है।

जिम्मेदार बातचीत को बढ़ावा देने, अफवाहों को रोकने, हमदर्दी बढ़ाने और साझा नैतिक मूल्यों की याद दिलाने के जरिए वे समाज को सहनशीलता और समझदारों के साथ जुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। अलग-अलग धर्मों के नेताओं का आसानी सहयोग इस हकीकत का व्यावहारिक संदेश देता है कि शांतिपूर्ण रह-आसितन में केवल मुक्ति है बल्कि समाज के लिए फायदेमंद भी है। स्थानीय स्तर पर शांति और भाईचारे की पहल सामाजिक प्रशनों को मजबूत करने के व्यावहारिक अवसर प्रदान करती है। सर्वधर्म साहचर्य, मोहल्ला स्तर की बैठकें, संयुक्त सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, पर्ववार संरक्षण की मुहिम, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य लोगों को मतभेदों के बजाय साझा मकसदों के इर्द-गिर्द इकट्ठा करने हैं। जब नागरिक अपने इलाके की बेहتری के लिए मिलकर काम करते हैं तो सहयोग और साझा अनुभवों के जरिए भरोसा स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। शैक्षणिक संस्थान भी विभाजनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ मजबूत समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं कराते बल्कि जिम्मेदार

नागरिकता, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सहमति का संस्कार भी देते हैं। ऐसे कार्यक्रम को साझा शैक्षणिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रसन्न बहस और समाज सेवा को बढ़ावा देते हैं, ये युवाओं में विविधता के महजुब और राष्ट्रीय जुड़ाव की भावना को मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय आयोजनों में मिलकर हिस्सा लेना भी एकता को बढ़ावा देने का असरदार माध्यम है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर साथ मिलकर भाग लेना नागरिकों को यह अहसास मिलता है कि भाषा, धर्म या सांस्कृतिक के अंतर के बावजूद ये एक साझा राष्ट्रीय पहचान और संवैधानिक निष्ठा रखते हैं। ये अवसर आजादी, समानता, भावधारों और न्याय जैसे उन मूल्यों की याद ताजा करते हैं जो पूरे देश को एक महजुब डोर में बांधते हैं।

भारत के राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और उनके योगदान को याद करना भी इस साझा निष्ठा की भावना को और मजबूत बनाता है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आझाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और अंगनगत अलम हस्तियों ने अलग-अलग

रहे अपना, लेकिन उन सबका मकसद भारत तक नहीं उठे। खुशहाली ही उनके जीवन का एक ही ध्येय बन गया। नगरों को सेवा, ईमानदारी, साहस और गणपति जिम्मेदारी जैसे नमूने को व्यक्तित्व समूहगत मतेधर्मे से ऊपर रखने की प्रेरणा दी है।

सामाजिक समावेशन (सोशल इनक्लूजन) का कार्यकर्मी सहयोग के लंबे अवरस पैदा करते हैं। युवाओं का नेतृत्व प्रशिक्षण, खेलकूद विनोदप्रतिभा, साहित्य उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विरासत को जानने-समझने के प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को साझा लक्ष्यों के लिए एक साथ काम करने का अवसर देते हैं। ऐसी गतिविधियाँ सामाजिक, आर्थिक विरासत और गतिविधियों सहयोग को बढ़ावा देती हैं और गलतफहमियों को दूर करने की संभावना को कम करती हैं।

प्रतिवार भी सामाजिक सोच और व्यवहार को बढ़ाने में बुनियादी भूमिका निभाते हैं। जो वे अपने घर में पढ़ाई करने का सम्मान करना, विधवाओं की कद्र करना और भारत की साझा धर्मपरीय विरासत पर गर्व करना सीखते हैं, वे जाड़े भारत ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं जो जाड़े जाड़े जाड़े को नकारते हैं और सकारात्मक

सामाजिक र्शितो को बढावा देते हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी में अरुण व्यूहार्, मेहमानवाजी और पड़ोसियों के प्रति फुल निभाने जैसे छोटे लेकिन जरूरी काम समाज के र्शितों को खामोशी से मजबूत बनाते हैं।

तनीकी के तेज विकास से भी हमारे मूल्यों पर गहरे और दूरगामी असर डालें हैं। आज की तेज रस्ता जिन्दगी में तनीकी की चकावीध से बढना नामुमकिन है, इसलिए इसका सही और जिम्मेदार इस्तेमाल ही हमें सही दिशा में आगे बढने और तरकी को हमें का रास्ता दिखारणा।

आर तनीकी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो यह सामाजिक सौहार्द को बढावा दे कि एक असरदार साधन बन सकती है। डिजिटल मंच अलग-अलग समुदायों के बीच सहयोग के सफल उदाहरण सामने लाने, सकारात्मक सामाजिक पहलुओं को उजागर करने और रचनात्मक बातचीत को बढावा देने के व्यापक असर देते हैं। इसके साथ ही जिम्मेदार डिजिटल व्यूहार् की मांग है कि किसी भी खबर या जानकारी को आगे बढाने से पहले उसकी पडताल की जाए, भडकाऊ सन्देशों से बां जा और टकराव के बजाय बातचीत को प्राथमिकता दी जाए।

यह बात समझनी होगी कि विभाजनकारी

प्रावृत्तियों के मुकाबले सामाजिक मजबूती जिम्मेदारी की जिंदगी में विपरीत, सहयोग और आनायासी सम्मान की आदतों से परवाना चढ़ती है। यह वागर्भिक स्कुलों, मोहल्लों, दफ्तरों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक जीवन में बढ़ा जिम्मेदारी की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो समाज और अधिक मजबूत बनता है। बाबूजी को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर शांति की पहलों का समर्थन करना, सामाजिक भागीदारी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, राष्ट्रीय स्तरों को मिल-जुलकर बनाना और बहारों के राष्ट्रीय नेताओं के जीवन में प्रेरणा लेना ऐसे मजबूत रिश्ते बनाते हैं जो मतभेदों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। यही मजबूत सामाजिक स्थिरता न केवल आपसी भावपूर्ण को बनाए रखती है बल्कि एक अधिक शांतिपूर्ण, कुलुट और समावेशी भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां विधिवत प्रेरणा के सबसे बड़ी ताकत बन रहे और यही मजबूत देश की सबसे बड़ी पहचान है जिस पर हमें गर्व है।

संक्षिप्तवार्ता

दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे वामपंथी छात्र संगठन

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने की मांग को लेकर पांच वामपंथी छात्र संगठन 10 अक्टूबर को यहां जंतर -मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में दी गई। बयान में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए), प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन (पीएसयू) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ब्लॉक (एआईएसबी) ने कहा कि वे बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

छेड़छाड़ की जांच होने तक एसीपी ने पदोन्नति लेने से किया इनकार

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उपराज्यपाल की तरफ से सोमवार को दिए गए एसीपी विवेक भगत की पदोन्नति (इयूटी वार्ज) को फिलहाल रोक दिया गया है। यह रोक विवेक भगत के अनुरोध पर ही लगाई गई है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों की जांच तक उनकी पदोन्नति के आदेश को लंबित रखा जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि बीते 5 अक्टूबर को विभिन्न एसीपी की पदोन्नति को लेकर जारी आदेश में बदलाव किया जा रहा है। इस आदेश के तहत दानिप्स के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का इयूटी वार्ज सौंपा गया था।

करीब 10 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी में आठ आरोपियों को जमानत

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। पटियाला हाउस कोर्ट ने करीब दस करोड़ रुपये के सोना तस्करी मामले में आठ आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी आरोपी से सोने की व्यक्तिगत बरामदगी नहीं हुई है और ऐसा कोई स्वतंत्र सबूत भी सामने नहीं आया है, जो बरामद सोने को सीधे तौर पर किसी आरोपी से जोड़ता हो। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। जमानत का मकसद ट्रायल में पेशी सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। मुख्य न्याधिक मंजिस्ट्रेट मुद्दल गुप्ता की कोर्ट ने आठ आरोपियों की जमानत अर्जियां मंजूर की। सभी को 50–50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक–एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

दो बार खोया पिंग स्मार्ट कार्ड तो फिर एक साल तक नहीं मिलेगा बसों में मुफ्त सफर

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। राजधानी में डीटीसी और परिवहन विभाग की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए पिंग स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में पिंग स्मार्ट कार्ड बनवा चुकी 19.18 लाख महिलाओं को इस कार्ड को सबंज कर रखना पड़ेगा। पिंग स्मार्ट कार्ड दो बार खोया तो फिर एक साल नया पिंग स्मार्ट कार्ड जारी नहीं होगा और बसों में मिलने वाली मुफ्त सफर की सुविधा पर भी एक साल तक के लिए ब्रेक लग जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग, नो-वैंडिंग जोन घोषित किया

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एक खास हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे इलाके को नो-हॉकिंग जोन और नो-वैंडिंग जोन घोषित कर दिया है।

कोर्ट ने 90 पहचाने गए वेंडर्स को तब तक किसी दूसरी जगह से काम करने को इजाजत दी है, जब तक कि टाउन वेंडिंग कमेटी-जब

नुक्कड़ नाटक के जरिए ट्रैफिक पुलिस ने 300 छात्रों को दिया सड़क सुरक्षा का पाठ

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उत्तरी रेंज ने मंगलवार को सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बख्तावरपुर स्थित मदर खजानी स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता

नरेला ट्रैफिक सर्कल के तहत आयोजित कार्यक्रम में करीब 300 छात्रों ने हिस्सा लिया। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के साथ व्यवहार करने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम डीसीपी ट्रैफिक उत्तरी रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देशन और निगरानी में आयोजित किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों को यातायात नियमों की अनदेखी से होने वाले सड़क हादसों और उनके गंभीर परिणामों के बारे में रोचक एवं सरल तरीके से समझाया गया। कलाकारों ने अभिनय के माध्यम से यह संदेश दिया कि सड़क पर छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन

छह घंटे में लूट की गुत्थी सुलझी, तीन आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। डीबीजी रोड थाना पुलिस ने लूट के एक मामले को छह घंटे के भीतर सुलझाते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान करोलबाग निवासी तुलसी (31), दीपक उर्फ चंपक (19) और उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी छोट्ट उर्फ डोरेमोन (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जबकि चार हजार रुपये की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर की रात करीब 10:15 बजे पीड़ित घर लौट रहा था। वह कलकादास चौक के पास पहुंचा, तभी तीन युवकों ने उसे घेर लिया। एक आरोपित ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने उसकी पैंट की जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। तीसरे आरोपित ने

उसकी शर्ट की जेब से चार हजार रुपये निकाल लिए। वारदात के बाद तीनों आरोपित मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर डीबीजी रोड थाना



पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक आरोपित के नाम तुलसी के बारे में जानकारी मिली। पुलिस टीम उसके झुग्गी स्थित टिकाने पर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इलाके में उसके संभावित टिकानों और आवाजाही वाली जगहों पर निगरानी बढ़ाई।

लागतार प्रयास और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने चार अक्टूबर को करोलबाग इलाके से तीनों आरोपितों को उनके संभावित टिकानों से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने लूट की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की।

दिल्ली पुलिस अधिकारी का फर्जी अश्लील एआई पोस्टर वायरल करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने एक पुलिस अधिकारी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कुत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से तैयार किया गया फर्जी और आपत्तिजनक पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में 24 वर्षीय नसीम को गिरफ्तार किया है।

आरोपित ने इस डिजिटल रूप से तैयार पोस्टर में पुलिस अधिकारी को एक महिला का यौन उत्पीड़न करते हुए दर्शाया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने पूछताछ और विस्तृत जांच के लिए उसे रिमांड पर ले लिया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मंजीत ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपित नसीम 10वीं फेल है, लेकिन खुद को सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पेश करता था। उसने इसी वर्ष अप्रैल में इंटरग्राम पर एक चैनल शुरू किया था, जिस पर करीब

24 हजार फॉलोअर्स और 1,226 पोस्ट मौजूद हैं। पुलिस उसके मोबाइल फोन को जब्त कर उसके सोशल मीडिया हैंडल, पोस्ट और संदेशों की तकनीकी जांच कर रही है।

निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को मिली नियमित जमानत

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। कॉंकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि जमानत की शर्तों का जिक्र करते हुए विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। इसके पहले 15 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को शर्तों के साथ तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी।

दिल्ली में अक्टूबर के पहले सप्ताह में डेंगू के 98 मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 695 पहुंचा

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)।

राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में डेंगू के 98 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इस वर्ष अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 695 हो गई है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

दिल्ली में सितंबर में इस बीमारी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे जब डेंगू के 286 मामले सामने आए थे। इसके अलावा मलेरिया के 124 मामले दर्ज किए गए थे। यह इस साल दोनों बीमारियों के एक महीने में सबसे अधिक मामले हैं। इससे पहले अगस्त में दिल्ली में डेंगू के 90 और मलेरिया के 53 मामले दर्ज किए गए थे

तीन अक्टूबर को समाप्त सप्ताह की



साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में अक्टूबर में अब तक डेंगू के 98 और मलेरिया के 23 मामले सामने आए हैं। इस साल मलेरिया के कुल मामलों की संख्या 266 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया



उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कई स्वास्थ्य सेवाओं का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आशा सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत के साथ-साथ आशा कार्यकर्ता का मासिक मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 6,000 किया गया है। उन्होंने अनमोल योजना का विस्तार, जीबी पंत अस्पताल में सोल्ट्रे सेंटर और नर्सिंग होम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकासि भारत के विजन के अनुरूप आज दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी अहम पहलों की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ंटलाइन आशा कार्यकर्ता की अहम भूमिका को देखते हुए उनके मासिक मानदेय को 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही नवजात शिशुओं की एडवर्ड्स स्क्रീनिंग के लिए अनमोल योजना का विस्तार किया गया है। इसके साथ-साथ जीबी पंत अस्पताल में एक समर्पित सोल्ट्रे सेंटर और नर्सिंग होम मैनेजमेंट के लिए एक पारदर्शी पोर्टल को भी शुभारंभ किया गया है।

शाहदरा फायरिंग में घायल जावेद निकला सीमापुरी हत्याकांड का वांटेड

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के शाहदरा जिले की पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाते हुए तीन बड़ी कार्रवाई की है। शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मोना ने इन कारवाइयों की जानकारी दी। इनमें देर रात हुई गोलीबारी की घटना का मामला, अवैध शराब की बड़ी खेप की जब्ती और एक सक्रिय वाहन चोर की गिरफ्तारी और पांच चोरी की दोपहिया गाडियों की बरामदगी शामिल हैं।

देर रात हुई फायरिंग और चाकू मारने की घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मोना ने बताया कि रात 9 बजकर 20 मिनट पर पुलिस को फायरिंग की कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां जावेद नाम का एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसे गोली लगी थी। उसके साथ मौजूद एक महिला पर चाकू से हमला किया गया था। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

जांच में सामने आया कि घायल जावेद खुद एक अपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। पिछले साल अक्टूबर में सीमापुरी थाने में हुए एक हत्या के मामले में वह वांटेड था और दिल्ली पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मोना ने कहा कि इस फायरिंग की घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दूसरी बड़ी कार्रवाई में शाहदरा जिले की एटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। डीसीपी ने बताया कि एनटीएफ के इंस्पेक्टर अर्जुन को सूचना मिली थी कि शाहदरा जिले में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की सप्लाई होने वाली है।

आए। दिल्ली में अगस्त में चिकनगुनिया के आठ और सितंबर में पांच मामले दर्ज किए गए थे। इन नए मामलों के साथ, दिल्ली में इस साल चिकनगुनिया के कुल मामलों की संख्या 29 पहुंच गई है। इस बीमारी से भी अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं है।

एमसीडी ने बताया कि मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए सभी रिहायशी इलाकों में मच्छर-निर्माण के उपाय किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों ने इस साल अब तक 3.18 करोड़ से अधिक बार घर का सर्वेक्षण किया और 1.89 लाख से अधिक घरों में लावा का पता लगाया है। निगम ने 1,32,172 कानूनी नोटिस जारी किए हैं, जबकि 20,882 चालान किए।

महिला पत्रकार उत्पीड़न मामला

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के प्रभार संबंधी आदेश में किया बदलाव

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। महिला पत्रकारों से उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े एक अधिकारी के अनुरोध के बाद, दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने वाले आदेश में संशोधन किया है।

अपने एक्स हैंडल पर जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, दिल्ली सरकार ने बताया कि 5 अक्टूबर, 2026 के एक आदेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (डीएनएपीएस) के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद का वर्तमान कार्यभार सौंपा गया था। अब सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत के संबंध में इस आदेश में संशोधन किया जा रहा है।

इन अधिकारियों को अतिरिक्त इयूटी का काम सौंपने का प्रस्ताव 25 अगस्त को ही शुरू कर दिया गया था, यानी उन हालिया घटनाओं से काफी पहले जिनकी वजह से लोगों का ध्यान इस ओर गया। 5 अक्टूबर, 2026 को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही इसके आदेश जारी किए गए। आदेश में बताया गया है कि वर्तमान कार्यभार सौंपना एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। इससे संबंधित अधिकारियों को कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता और न ही उन्हें उस पद पर नियमित रूप से काम करने वाले अधिकारियों की तरह कोई कानूनी जिम्मेदारी निभाने की इजाजत मिलती है।

विवेक भगत ने अपनी स्वेच्छा से अनुरोध किया है कि महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामले में पूरी जांच होने और उसके सतोषजनक रूप से संभल होने तक वे वर्तमान कार्यभार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उनके अनुरोध को देखते हुए 5 अक्टूबर के आदेश में बदलाव किया जा रहा है और इसे केवल बाकी बचे 11 अधिकारियों के लिए फिर से जारी किया जाएगा। यह घटनाक्रम महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार की खबरों के बाद दिल्ली पुलिस की बढ़ती जांच-पड़ताल के बीच सामने आया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि मूल प्रस्ताव इस विवाद से पहले का था और यह व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी है। उम्मीद है कि जल्द ही बदला हुआ आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें जांच का नतीजा आने तक अधिकारी के पद से अलग होने का फैसला शामिल होगा। अधिकारियों ने फिर से कहा कि अस्थायी चार्ज के साथ कोई वित्तीय या कानूनी फायदा नहीं मिलता है, जिसका मतलब है कि इस व्यवस्था का दायरा सीमित है। जांच की प्रगति या उसके बाद की किसी प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि अतिरिक्त चार्ज सौंपने की प्रक्रिया हाल के आरोपों से अलग, तय नियमों और समय-सीमा के अनुसार की गई थी।

संक्षिप्तवार्ता

सेवा संकल्प अभियान में दिव्यांगों को मिला सहारा, 81 को बांटे सहायक उपकरण

औरैया, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में सेवा संकल्प अभियान के अंगरंगत मंगलवार को विकासखंड बिधूना में दिव्यांगजन लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी राम कुपाल चौधरी एवं खंड विकास अधिकारी ने दिव्यांगजन लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए।

राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके सशक्तीकरण एवं स्वावलंबन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सहायक उपकरण दिव्यांगजनों की दैनिक गतिविधियों को सुगम बनाने के साथ उनकी गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही



वेब वार्ता, बहराइच। पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण में पश्चारी निरीक्षक हरन्द कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस व सॉट की संयुक्त

त्योहारों में नई परंपरा शुरू न करें, अफवाहों से बचें: जिलाधिकारी

औरैया, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला और दीपावली समेत आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई।

जिलाधिकारी वृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मगुरुओं, आयोजन समितियों के पदाधिकारियों, पीस कमेटी सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी करीब डेढ़ माह तक विभिन्न पर्व और धार्मिक आयोजन होने हैं। सभी त्योहार जिले में परंपरागत रूप से शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस बार भी मिल-जुलकर त्योहार मनाने तथा किसी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करने की अपील की। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान



किसी भी प्रकार की नई परंपरा या नई गतिविधि शुरू न की जाए। आयोजन पूर्व निर्धारित और पारंपरिक तरीके से ही किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी किसी स्थिति की जानकारी मिलने पर संबंधित लोगों से तत्काल संवाद कर समाधान कराया जाए। साथ ही बिना सत्यापन कोई सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करने को कहा।

रामलीला आयोजनों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि रात में होने वाले आयोजनों के दौरान मुख्य मार्गों पर भीड़ एकत्र न हो। प्रवेश और निकास की पंखांत व्यवस्था के

साथ यातायात सुचारु रखा जाए। एरवा कटरा क्षेत्र में करीब 15 रामलीलाओं को देखते हुए आयोजन स्थलों, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का पूर्व परीक्षण कराने को कहा गया। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर डीएम ने नदियों में सीधे विसर्जन पर रोक लगाने और चिन्हित सुरक्षित स्थानों पर अस्थाई तालाब बनाकर विसर्जन कराने के निर्देश दिए। बच्चों को नदी, तालाब और गहरे पानी के आसपास जाने से रोकने तथा विसर्जन में जिम्मेदार वयस्कों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने पूजा पंडालों और रामलीला स्थलों

पर अग्नि सुरक्षा मानकों की जानकारी दी। डीएम ने पर्याप्त प्रवेश-निकास द्वार, आपात रास्ते, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और अग्निशमन उपकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को अस्थाई कनेक्शन और तारों की जांच के निर्देश भी दिए गए।

और प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहे

पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत विक्रेताओं से कराने, दुकानों का पूर्व निरीक्षण करने तथा अवैध भंडारण या बिना अनुमति बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धार्मिक जुलूसों के निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने तथा पूर्व विवाद वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण, निगरानी और सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा समेत प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, निकायों के अधिकारी, धर्मगुरु और प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहे।



डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण

वेब वार्ता, बहराइच। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर संयुक्त कार्यालय, अभिलेखागार, उप निबंधक कार्यालय सहित विभिन्न पटलों एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों में साफ-सफाई, अभिलेखों के रख-रखाव तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया।

कलेक्ट्रेट में विधवा पेंशन से सम्बन्धित समस्या लेकर पहुंची महिला से जिलाधिकारी ने स्वयं मुलाकात कर उसकी समस्या जानी। इसके बाद जिलाधिकारी महिला को अपने साथ सम्बन्धित पटल पर ले गए तथा उसके पेंशन प्रकरण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए पात्र महिला को पेंशन का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न कार्यालयों में साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं में कमी मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को नियमित रूप से साफ-सफाई कराने तथा कार्यालयों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। उप निबंधक कार्यालय में भी उन्होंने कार्यप्रणाली एवं अभिलेखों की स्थिति का जायजा लिया।

हरदोई में पुलिस की बड़ी कामयाबी: 220 गुम मोबाइल बरामद, 40 लाख के फोन स्वामियों को लौटाए

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। गुम हुआ मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे मंगलवार को उस समय खिल उठे, जब हरदोई पुलिस ने सर्विलांस सेल और सीईआईआर पोर्टल की मदद से बरामद किए गए 220 मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में जनपद में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सर्विलांस सेल ने जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइल फोन के



संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर तकनीकी माध्यम से कार्रवाई शुरू की। पुलिस की लगातार निगरानी और तकनीकी प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन माह में

220 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये है।

6 अक्टूबर को पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा

सर्विलांस सेल की ओर से बरामद किए गए सभी 220 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द किए गए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई।

पुलिस के अनुसार, गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में सर्विलांस सेल और सीईआईआर पोर्टल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तकनीकी सूचनाओं के आधार पर मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद करने की कार्रवाई की गई।

तकनीकी स्तर पर किये जा रहे हैं प्रभावी प्रयास

पुलिस को इस कार्रवाई से न केवल गुम मोबाइल फोन के स्वामियों को राहत मिली, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में पुलिस को सूचना देकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने पर उसकी बरामदगी के लिए तकनीकी स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

जनसुनवाई में 141 शिकायतें प्राप्त

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। आज जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को सुना। जनसुनवाई में कुल 141 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का सम्यक्बद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों एवं नगर पालिका के अधिकारियों की वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थिति ली। उपस्थिति के दौरान कुछ अधिकारियों के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

छोटे कुनबे और सिमटती खेती: गांवों में छाई वीरानी, वैस्ट यूपी में बदला परिवार का स्वरूप; खेतों में मशीनें बढ़ीं, पर रिश्तों की रौनक घटी

... और गांव के द्वार सूने नजर आने लगे हैं

हापुड़ जिले में सिंभावली क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख महाराज सिंह के परिवार का उदाहरण गांव से शहर की ओर बढ़ते इस बदलाव को साफ दिखाता है, जिनकी नई पौड़ी दिल्ली, गाजियाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बस चुकी है। लोनी (गाजियाबाद) ब्लॉक प्रमुख रहे महाराज सिंह परिवार के सुरेश, तपसी कसाना तथा राजकुमार मेरठ के नजदीक पंचली गांव में सतबीर सिंह, ओमबीर सिंह, पूर्व प्रधान अनिल सिंह, हापुड़ जिले के बड़े गांव नानपुर नंबरदार छतरसिंह परिवार के योगेन्द्र सिंह, ऋषिपाल सिंह, राजपुर मंडैय्या निवासी हरबीर सिंह, प्रधान देवेन्द्र सिंह, रविंद्र चौधरी और गोहरा मुदाफरा के वीर सिंह समेत ग्रामीणों के अनुसार गांवों में जमीन और मकान तो बचे हैं, लेकिन युवा शहरों में चले गए हैं। इससे गांवों में रिश्तेदारी और आपसी सामाजिक मेलजोल का पुराना स्वरूप भी बदल रहा है और गांव के द्वार सूने नजर आने लगे हैं।

वहल-पहल बीते दिनों की बात रह गई है। स्थानीय स्तर पर किसानों और ग्रामीण परिवारों से हुई बातचीत में मुरादाबाद के अशोक गुर्जर पटेल, अमरोहा के देहरा चक निवासी चौधरी परविंदर सिंह, चौधरी नरेश

सिंह, देहरी गांव के कैलाश गुर्जर, मुक्रीमपुरा के अमरपाल सेनी, मोहदौनपुर के जितेंद्र कटारिया, गजरौला के जयकरण सेनी, चकनवाला के महाशय जयचंद व जैनुल आबेदीन, तिगरिया भूड़ के रणबीर सिंह,

राजपाल सिंह और डॉ. मनोज कटारिया, संभल के चौधरी रामपाल सिंह, रामपुर के राजेश गंगवार, सहारनपुर मंडल के देवबंद ब्लाक प्रमुख रहे चतर सिंह परिवार के प्रसिद्ध गांव मिरापुर निवासी डॉ विजय पवार, रामपुर महिहारान के राजीव पवार, मुकुल पवार, बागपत जिले के बोढ़ा गांव निवासी मास्टर देवप्रकाश एवं पधान कुलदीप सिंह तथा मेरठ के बड़े किसान रणसिंह एडवोकेट से हुई बातचीत में भी छोटे परिवार की बढ़ती प्रवृति पर विस्तृत चर्चा हुई।

किसानों के मुताबिक पहले ज्यादा बच्चे होने का मतलब खेत और पशुपालन के कामों के लिए घर में अधिक हाथ होना था। अब परिवार छोटे हो गए हैं और बच्चे पढ़ाई या

नौकरी के सिलसिले में शहरों को रुख कर रहे हैं, जिससे पैतृक खेती का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। हल-बैल की जगह ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है और पारिवारिक श्रम की कमी को पूरा करने के लिए बाहरी तथा प्रवासी मजदूरों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

किसानों के अनुसार छोटे परिवार अपनाने की एक बड़ी वजह जमीन का लगातार होता बंटवारा भी है। आठ-दस बच्चों के बीच कृषि भूमि बंटने पर जोत बेहद छोटी हो जाती है, जिससे खेती से परिवार की जरूरतें पूरी करना बेहद कठिन हो जाता है। इसी सामाजिक और आर्थिक बदलाव के बीच बातचीत में नई रुचि दिखाई दी है।

हरदोई मे ई-रिक्षा पंजीकरण पर घमासान, तीन माह से लंबित मामलों के समाधान की मांग; आंदोलन की चेतावनी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। ई-रिक्षा चालकों और डीलरों की समस्याओं को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रामज्ञान गुप्ता ने मंगलवार को ई-रिक्षा डीलरों के साथ सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) अरविंद कुमार सिंह से मुलाकात की। व्यापारियों ने ई-रिक्षा पंजीकरण में आ रही कथित दिक्कतों और करीब तीन माह से लंबित पंजीकरण का मुद्दा उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।

रामज्ञान गुप्ता ने आरोप लगाया कि ई-रिक्षा पंजीकरण के लिए चालकों से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने को कहा जा रहा



है। उनका कहना है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर चालकों से 10 से 12 हजार रुपये तक लिए जा रहे हैं, जबकि

धरना शुरू करने होंगे मजबूर

उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब और छोटे व्यापारियों को राहत देने के बजाय उन पर नियमों का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-रिक्षा बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के लिए रोजगार का साधन है, इसलिए पंजीकरण संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। व्यापार नेता ने कहा कि यदि तीन माह से लंबित ई-रिक्षा पंजीकरण जल्द शुरू नहीं किए गए तो डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।

सरकारी शुल्क करीब 1,500 से 2,000 रुपये बताया जा रहा

दूध से पनीर तक संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक जरूरी :

पो. सुधीर सिंह

जौनपुर, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वचल विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में संचालित फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संरक्षण विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के पूर्व वैज्ञानिक प्रो. सुधीर सिंह ने विद्यार्थियों को दुग्ध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादों के संरक्षण की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का दैनिक मात्रा में सेवन किया जाता है। ऐसे में इनकी गुणवत्ता, पोषणामक मूल्य और खुराक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दूध, पनीर के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है।

नवरात्रि पर्व पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की मांग

मुरादाबाद/वेब वार्ता। आगामी नवरात्रि पर्व को श्रद्धा, धार्मिक आस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाजरंग दल की महानगर मुरादाबाद इकाई द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन पेश किया गया

जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से मंदिरों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने की मांग की। ऐसे में इनके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने, निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा मंदिरों तक जाने वाले मार्गों को



अतिक्रमण एवं अव्यवस्था से मुक्त कर यातायात व्यवस्था सुचारु रखने पर जोर दिया गया है

यह भी मांग की गई है कि नवरात्रि पर्व के दौरान मंदिरों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों

के आसपास तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में मांस एवं मदिरा की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं दीपावली, अजय, भूप सिंह, विष्णु, अमिता चोधरी, शनि, सुमित सेनो, छोट्ट, आकाश, एवं प्रिंस सहित अनेक कार्यक्रमों में

आयोजकों द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस एवं निगरानी व्यवस्था करने की मांग की गई

इनकी रही उपस्थिति

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना के अलावा सुरेश गुप्ता शरद रस्तोगी विजय शर्मा, गोविंद सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, दिशांत सेनी, जितन प्रजापति, सुशांत गुप्ता, अनुज आर्य, अक्षय शुक्ला, शिवम प्रजापति, किशन सिंह, अतुल, दीपांशु, सुमित, अजय, भूप सिंह, विष्णु, अमित चौधरी, शनि, सुमित सेनो, छोट्ट, आकाश, एवं प्रिंस सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



मुरादाबाद/वेब वार्ता

कोचिंग संस्थान स्कॉलर डेन और उसके निदेशक विवेक ठाकुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अभिभावक सतीश कुमार आर्य ने मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संस्थान ने शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलने के बाद न तो निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराई और न ही फीस वापस की।

शिकायत के अनुसार, सतीश कुमार आर्य ने अपने पुत्र मृगांक सिंह के प्रवेश के लिए संस्थान को कुल 1,51,000 का भुगतान किया। इसमें 8 दिसंबर 2025 को 85,000, 1 मई 2026 को 30,000 तथा 2 जून 2026 को 36,000 की राशि शामिल है। शिकायतकर्ता ने संबंधित रसीदों का भी उल्लेख किया है।

प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि जिस भवन में कोचिंग संचालित की जा रही थी, उसे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कपड़े के शोरूम के लिए स्वीकृति दी गई थी। आरोप है कि भवन का उपयोग नियमों के विपरीत कोचिंग संस्थान के रूप में किया गया। शिकायतकर्ता ने मोताबिक, एमडीए द्वारा संस्थान को दो माह के लिए सील भी किया गया था। साथ ही अग्निशमन विभाग की ओर से भी सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया गया है।

महत्वपूर्ण ख़बर

अमेरिका, चीन और रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने की कर रहे प्लानिंग

■ वाशिंगटन। भारत जैसे देश में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अभी तक पर्याप्त संख्या में न्युक्लियर रिएक्टर डेवलप नहीं किए जा सके हैं। वहीं, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश धरती तो छोड़िए अब चांद पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि चांद पर भेजे गए मिशन को लंबे समय तक एनर्जी मिलता रहे, इसलिए इस मिशन पर काम किया जा रहा है। साल 2030 तक चांद पर न्युक्लियर पावर रिएक्टर स्थापित भी कर दे। वहीं, रूस और चीन साथ मिलकर यह काम साल 2036 तक कर सकते हैं। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या चांद के भूभाग पर अधिकार का दावा किया जा सकता है? दरअसल अमेरिका, चीन और रूस चांद पर परमाणु रिएक्टर विकसित करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इन देशों का मानना है कि लंबे समय तक चांद पर बैस स्थापित करने, वहां के संसाधनों की खोज और अंतरिक्ष में आगे के मिशनों को समर्थन देने के लिए भरोसेमंद परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण होगी।

एसआईआर के खिलाफ 19 दलों का सेव डेमोक्रेसी मार्च

एआईआर के बाहर रोके गए विपक्षी सांसद, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा द्वा के नारे

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को तेज हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 19 विपक्षी दलों के सांसदों ने सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाला। संसद के मकर द्वार से निर्वाचन आयोग की ओर बढ़े सांसदों को पुलिस ने ऑल इंडिया रेडियो के बाहर रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसद सड़क पर बैठ गए।

विपक्षी सांसद सेव डेमोक्रेसी का बैनर लेकर मार्च में पहुंचे। इस दौरान ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। राहुल गांधी के हाथ में ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो लिखा पोस्टर भी दिखाई दिया। मार्च को देखते हुए संसद मार्ग, जंतर-मंतर और निर्वाचन आयोग कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि वे



एसआईआर प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और फॉर्म-6 से जुड़े अपने सवाल निर्वाचन आयोग के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने फॉर्म-6 में कथित बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग का कहना है कि फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि एसआईआर

सांसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च में आप और डीएमके शामिल नहीं

प्रक्रिया के तहत एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र को व्यवस्था की गई है। विपक्ष के मार्च पर शिवराज का पलटवार

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस चुनावी व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसी व्यवस्था के तहत केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दलों को जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुनावी नतीजों को स्वीकार कर

लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।

आप और डीएमके मार्च से बाहर

नई संसद से निर्वाचन आयोग तक निकाले जा रहे इस मार्च में आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद प्रदर्शन में पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन ने 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी अभियान के तहत विरोध कार्यक्रमों का ऐलान किया था, जिसमें 6 अक्टूबर को सांसदों के निर्वाचन आयोग तक मार्च को योजना शामिल थी। इससे पहले 11 अगस्त 2025 को भी विपक्षी दलों ने संसद भवन से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला था। उस प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत विपक्ष के कई दलों के नेता शामिल हुए थे। मौजूदा प्रदर्शन के साथ एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर सामने आया है।



भ्रष्टाचार से घिरी पंजाब सरकार, राहत के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें मुख्यमंत्री के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) भी शामिल हैं, पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद पंजाब में सियासी भूचाल आ गया है। इस आदेश को अपनी सरकार पर सीमा हमला मानते हुए भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह पुष्टि की थी कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा साझा किए गए दस्तावेज प्रथम दृष्टया इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का संकेत देते हैं, जिसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच सौंपना उचित होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कई बदंशत नहीं की अपनी नीति का लगातार दावा करती रही है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह दिल्ली ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से तत्काल इस्तीफे की मांग की। दिल्ली ने आरोप लगाया कि अदालत के फैसले ने आप सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इसी तरह, पंजाब कांग्रेस के नवनिर्भुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और जोर दिया कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की देरी या राजनीतिक दबाव की गुंजाइश न हो। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा।

अपनी पार्टी बनाएंगी पूर्व आईएस दिव्या मित्तल

लखनऊ। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) से इस्तीफा देने के बाद दिव्या मित्तल ने राजनीति के मैदान में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी सरगमीं और तेज हो गई है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किसी स्थापित राजनीतिक दल में शामिल होगी या अपनी नई पार्टी बनाएंगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह किसी मौजूदा दल में जाने के बजाय अपनी पार्टी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खोलेगा, जिससे चुनावी समीकरणों में और अधिक जटिलता आएगी। दिव्या मित्तल के साथ ही, नगीना सांसद चंद्रशेखर पर कई आरोप लगाकर



चर्चा में आई रोहिणी धावरी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में सक्रिय दिखाई देगी। रोहिणी भी स्वटजरलैंड से लौटने के बाद लखनऊ सहित कई इलाकों में सक्रिय हुई हैं और पारसी समाज के अधिकारों की आवाज बुलंद करती दिखाई देगी। हालांकि उन्होंने अभी

किसी सीट से चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अनुकूल हैं कि सच ठीक रहा तो वह भी चुनावी समर में उतर सकती हैं। दिव्या मित्तल मिजापूर या बलिया में अपने लिए मुफ़ीद विधानसभा सीट तलाश रही हैं। उनकी एंटी और रोहिणी धावरी की सक्रियता से 2027

के चुनाव में नए चेहरों और नई विचारधाराओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। 2027 में होने वाले इन चुनावों के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव फरवरी-मार्च में हो सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की तरफ से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाना बाकी है। दिव्या मित्तल जैसी नई शख्सियतों का राजनीतिक मैदान में उतरना, और छोटे दलों व नए मोर्चों का सक्रिय होना, यह संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जहाँ पारंपरिक राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पर नए सिर से विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश, जो भारत के सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटों वाला

राज्य है, में जितने ज्यादा मोर्चे खुलेंगे, स्थापित दलों के लिए उतनी ही दिक्कतें बढ़ेंगी। दरअसल, इन नए मोर्चों या पार्टियों द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी कुछ हद तक स्थापित दलों के उम्मीदवारों के वोटों पर असर डाल सकते हैं, जिससे उनका जीत का गणित बिगड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के पहले अपने कुनबे में ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को शामिल करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मोर्य की अपना समाज पार्टी और पल्लवी पटेल की अपना दल (कमेरावादी) जैसी पार्टियां इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। कांग्रेस तमाम लोगों को पार्टी में शामिल भी करवा रही है, जिसका सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा ताकि संभावित वोट-कटवा असर को कम किया जा सके।

वाशिंगटन। रूस के साइबेरिया स्थित इरकुत्स्क क्षेत्र में एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की महिला लैब टेक्नीशियन दर्या शिपिलोवा की संदिग्ध मौत के बाद संभावित प्लेग संक्रमण को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद से जहां मध्य एशिया में हाई अलर्ट घोषित किया गया है वहीं अमेरिका ने सीधे तौर पर रिपोर्ट मांगी है। ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इरकुत्स्क स्थित संस्थान में लैब कर्मचारी की मौत के मामले पर नजर रखने की बात कही है। करीब 95 शोधकर्ताओं वाला यह संस्थान साइबेरिया और रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में गंभीर संक्रमणों की रोकथाम और निगरानी से जुड़ा प्रमुख केंद्र है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वह सीडीसी के साथ संभावित निमोनिक प्लेग से जुड़ी मौत की स्थिति की निगरानी



कर रहा है और रूस से मामले की सटीक जानकारी साझा करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रयोगशाला में काम के दौरान जीवित बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब टूटने के बाद वह कथित तौर पर संक्रमित हुई थी और बाद में उनकी मौत हो

गई। हालांकि, रूसी स्वास्थ्य निगरानी संस्था रोस्पोटबनादजोर ने प्लेग से मौत की पुष्टि नहीं की है। संस्था का कहना है कि महिला की मौत अज्ञात निमोनिया से हुई और जांच किए गए नमूनों में घातक रोगाणु नहीं मिला।

भारतीय लोग पाकिस्तानियों से जीते हैं ज्यादा, बांग्लादेश, अमेरिकियों से है कम



नई दिल्ली। भारतीयों की औसत उम्र पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा के लोगों की तुलना में कम। 2023 में भारत में जन्म के समय औसत उम्र 71 साल थी, जबकि पाकिस्तान में यह 68.2 साल, बांग्लादेश में 72.7 साल, अमेरिका में 78.5 साल और कनाडा में 81.4 साल थी, लेकिन ज्यादा समय तक जीने का मतलब हमेशा अच्छे सेहत के साथ ज्यादा साल ज़िंदा नहीं होता है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में स्वस्थ जीवन की औसत अवधि 60.6 साल थी, जबकि 2019 में यह 60.5 साल थी। 2021 में यह घटकर 58.4 साल हो गई थी और फिर 2022 में सुधरकर 60.2 साल हो गई। ये आंकड़े डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स का हिस्सा हैं, जिन्हें हाल ही जारी किया गया है। इनमें 2000 से 2023 तक औसत उम्र, स्वस्थ जीवन की औसत अवधि, मौत के कारण और बीमारी के बोझ जैसी जानकारी शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वैश्विक औसत उम्र महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच गई है, जबकि स्वस्थ जीवन की औसत अवधि में सुधार धीमी गति से हुआ है।

लखनऊ एयरपोर्ट की मजदूर कॉलोनी में भीषण आग, दो मजदूर झुलसे

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में मंगलवार सुबह मजदूरों की लेबर कॉलोनी में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे परिसर में धुआं और लपेटें दिखाई देने लगीं। घटना के बाद मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में टाटा प्रोजेक्ट्स की ओर से मजदूरों के रहने के लिए पीवीसी पैनल से तीन मंजिला आवास तैयार

किया गया था। इस भवन में करीब 352 मजदूर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह एक मजदूर सिलेंडर पर खाना बना रहा था, इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे आवास को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग फैलने की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद मजदूरों को तत्काल बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, अपना सामान बचाने की कोशिश में निर्मल और



राहुल नाम के दो मजदूर झुलस गए।

दोनों को उपचार के लिए अस्पताल

पाक-तुर्की की सऊदी में तैनाती: हूती हमलों के बीच एक्टिव हुआ मक्का समझौता

रियाद। सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के एक के बाद एक बढ़ते हमलों के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पहली बार सक्रिय हो गया है। इस समझौते की शर्तों के तहत पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब में अपनी सैन्य टुकड़ियों भेजने का निर्णय लिया है। यह अहम फैसला रियाद में आयोजित एक आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया, जिसमें तीनों देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। पाकिस्तान की ओर से सेना प्रमुख फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बैठक में हिस्सा लिया। तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर हूती विद्रोहियों के हमलों की कड़ी निंदा की और स्पष्ट किया कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।



सहमति बनी थी, जिसका मुख्य प्रावधान नाटो के आर्टिकल 5 के समान है। इसके तहत किसी भी

सदस्य देश पर हुए सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, जिससे अन्य देशों को

स्वतः ही बचाव के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। यह समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते के करीब एक महीने बाद ही पाकिस्तान और तुर्की के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित करने की घड़ी आ गई है, खासकर पाकिस्तान के लिए जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आलोचना का सामना कर रहा था। हूती हमलों पर तुर्पी साधने के लिए पाकिस्तान की लगातार आलोचना हो रही थी, जिसके बाद अब उसने सऊदी अरब की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तीनों देशों ने समझौते की शर्तों को तत्काल जमीनी स्तर पर लागू करने और सैन्य टुकड़ियों को सऊदी अरब भेजने पर सहमति जताई है।

संबित पात्रा का विपक्ष पर हमला, बोले- संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहा विपक्ष

इंडिया ब्लॉक के चुनाव आयोग तक मार्च के बीच भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राहुल गांधी को लेकर भी किया दावा

नई दिल्ली। इंडिया ब्लॉक के मंगलवार को सांसद से निर्वाचन आयोग तक निकाले जा रहे मार्च के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजित पात्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहा है और पिछले कुछ समय से

निर्वाचन आयोग को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। पात्रा ने कहा कि विपक्ष की ओर से लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की कोशिश नई नहीं है। उनके अनुसार, समय-समय पर सेना, उच्चतम न्यायालय, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), ईवीएम और हिंदुओं को लेकर भी विपक्ष को ओर से सवाल उठाए गए हैं। अब निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर

राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से राहुल गांधी को लॉन्च और दोबारा लॉन्च करने की कोशिश करती रही है। पात्रा का दावा है कि जब इन प्रयासों से अपेक्षित राजनीतिक परिणाम नहीं मिले तो विपक्षी दलों ने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का रास्ता अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि



विपक्ष की ओर से देश में

अस्थिरता का माहौल बनाने की

सेना और ईवीएम का भी किया जिक्र

संबित पात्रा ने कहा कि भारतीय सेना, उच्चतम न्यायालय, एचएएल और ईवीएम जैसे संस्थानों तथा व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सप्ताह से निर्वाचन आयोग को लेकर भी इसी तरह का अभियान चल रहा है। उनके मुताबिक, भाजपा का मानना है कि निर्वाचन आयोग के मुद्दे को लेकर विपक्ष राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अपने बयान के दौरान पात्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम का संदर्भ लेते हुए भगवान गणेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की मदद हड़तालें जीऊ नहीं, बल्कि हड़तालें जीऊ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में सही और गलत को समझने की क्षमता है और वे अपने विवेक के आधार पर मतदान करेंगे। पात्रा ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता तय करेंगे कि उन्हें किसे समर्थन देना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का भी हवाला दिया, जिसमें देश को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात कही जाती है।

कोशिश की जा रही है। हालांकि, जिन पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा चुके हैं, जिन पर विपक्ष की ओर से आरोपितियां और जवाब सामने आते रहे हैं।

समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा बस्तर : विजय शर्मा

➤ **जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री, हितग्राहियों को मिले योजनाओं के लाभ**

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अंचल नक्सलवाद के लंबे और काले दौर से निकलकर अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आज शासन की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं। विकास के साथ लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का नया वातावरण बन रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज जगदलपुर के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही स्थान पर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को वित्तीय सहायता, अधिकार अभिलेख, प्रमाण पत्र और विभिन्न योजनाओं का



लाभ प्रदान किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मां दैतेश्वरी की कृपा और शासन-प्रशासन के साझा प्रयासों से बस्तर में माओवादी हिंसा समाप्ति की ओर है। क्षेत्र में अब भय के स्थान पर विश्वास और हिंसा के स्थान पर विकास एवं सेवा का नया सवेरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने नक्सली हिंसा और आईईडी विस्फोटों से प्रभावित आम नागरिकों एवं सुरक्षा जवानों के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन दिवसीय विशेष

शिविर के माध्यम से पीड़ितों और दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण शत-प्रतिशत नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस पहल से जुड़े एक भावुक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि कृत्रिम हाथ लगने के बाद एक हितग्राही ने उसी हाथ से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया। वर्षों बाद अपने हाथ से सामान्य काम कर पाने की यह खुशी बताती है कि ऐसी पहल किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में विभिन्न विभागों ने मौके पर ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया। राज्यस्व विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पांच बाद प्रभावितों को कुल 6 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही 35 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। श्रम विभाग द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को 20 हजार रुपए तथा मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत एक पात्र हितग्राही को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर में हुए शामिल

➤**केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के नर्मदा में दो दिवसीय आयोजन**

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव गुजरात के नर्मदा में आज से शुरू हुए सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल हुए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गतिशक्ति से प्रगति थीम पर इसका आयोजन किया गया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी इस दौरान मौजूद थे। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपरा सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव



और राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर कश्यप भी चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। चिंतन शिविर में भाग ले रहे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने आज तीन सत्रों में भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, गुणवत्ता, रोड सेफ्टी और परियोजना प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से जगदलपुर, बिलासपुर से रायगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और रायपुर से सारागढ़ तक फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। चिंतन शिविर में निर्धारित किए जाने वाले फ्रेमवर्क्स से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

‘सरकार आपके द्वार’ से गांवों तक पहुंचीं सेवाएं जावलपुर के शिविर में मिला योजनाओं का लाभ

➤**राजस्व से स्वास्थ्य तक एक ही जगह मिली सेवाएं, लखपति दीदियों का सम्मान और हितग्राहियों को सहायता सामग्री का वितरण**



रायपुर। ‘सरकार आपके द्वार’ से गांवों तक पहुंचीं सेवाएं, जावलपुर के सेवा सेतु शिविर में एक ही स्थान पर मिला योजनाओं का लाभ ‘सरकार आपके द्वार’ से गांवों तक पहुंचीं सेवाएं, जावलपुर के सेवा सेतु शिविर में एक ही स्थान पर मिला योजनाओं का लाभ सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के माध्यम से शासकीय योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के और करीब पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के अटल समरस्ता, भवन जावलपुर में विशेष सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं की जानकारी और योजनाओं की जानकारी ली तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

रायपुर कॉर्पोरेशन वॉलीबॉल टीम के लिए बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का चयन 10 को



उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तथा वॉलीबॉल खेल को प्रोत्साहन मिलेगा।

ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए भूमि आरक्षण और किफायती आवास उपलब्ध कराने मंछ छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय सम्मान

प्रधानमंत्री के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता से कर रहा साकार : मुख्यमंत्री



रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है। विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (स्व) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) श्री सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के

परिवारों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति, भूमि की उपलब्धता, निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्व तथा नगरीय विकास विभागों की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर

सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने की हमारी पहल को मिली यह पहचान राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और परिणामोंमुख कार्यशैली का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। पक्का घर केवल चार दीवारों और छत नहीं, बल्कि एक निवास को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे और

घर बैठे वाहन संबंधी आवश्यक कार्य पूर्ण करने की मिलेगी सुविधा : मंत्री केदार कश्यप



रायपुर। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने सोमवार को बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत परसाभेदर में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। राज्यस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम देने के उद्देश्य से सोनबरसा जंगल सफारी के लिए 4 नई जियसियों और परिसर के सौंदर्यीकरण तथा अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई। लोकार्पण के पश्चात मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जगप्रतिनिधियों ने सर्वसुविधायुक्त नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन के विभिन्न कक्षों का अवलोकन

किया। मंत्रीद्वय ने भवन की उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण शैली की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए अधिकारियों को आम जनता की सहायता और नागरिक केंद्रित सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार जन-आकांक्षाओं को

प्राथमिकता देते हुए परिवहन सेवाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। आने वाले समय में परिवहन विभाग से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित होंगे, जिससे नागरिकों को अपने आवश्यक कार्य घर बैठे ही पूर्ण करने की अतृप्तपूर्व सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीकृत 2 लाख 14 हजार से अधिक वाहनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यातायात नियमों के पालन पर विशेष बल दिया। विशेषकर स्कूली बच्चों द्वारा वाहन चलाणे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए संचालित श्रावहीर योजनाश्र का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त एवं केशलेस इलाज की व्यवस्था दी जा रही है।

बस्तर में उम्मीदों की नई उड़ान, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय हेतु वृहद शिविर का आयोजन नक्सली हिंसा के दौर से बाहर निकलकर विकास की नई दिशा में अग्रसर : सीएम साय

रायपुर। आईईडी विस्फोटों के शिकार हर नागरिक को पैरों पर खड़ा करना ही नक्सलवाद की अंतिम निशानी को मिटाना – उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा लंबे समय तक नक्सल हिंसा और बारूदी सुरंगों की विभीषिका झेलने वाला बस्तर अब अंधकार से निकलकर शांति, विश्वास और विकास के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर के धरमपुरा त्रौड़ा परिसर में आयोजित तीन दिवसीय विशाल नि:शुल्क दिव्यांगजन सहायता एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर ने पीड़ितों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जारी ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में संभाग के बस्तर, कोण्डागंवा, नारायणपुर एवं कांकेर जिले से 3,800 से अधिक जरूरतमंदों का पंजीयन हुआ है, जिसके माध्यम से नक्सल विस्फोटों, सड़क दुर्घटनाओं व अन्य कारणों से अपने अंग गंवा चुके नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। शिविर को वचुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर लंबे समय तक नक्सली हिंसा के दंश से जूझा है, लेकिन अब यह अंचल उस दौर से बाहर निकलकर विकास की नई दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सर्शकिकरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। उन्होंने हिंसा में अपने अंग गंवा चुके पीड़ितों को आश्वास



करते हुए कहा कि वे खुद को कभी भी अकेला न समझें, पूरी सरकार और समाज पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार का लक्ष्य केवल बस्तर को हिंसा से मुक्त कराना नहीं, बल्कि एक शांत, सशक्त और श्किस्ति बस्तरश का निर्माण करना है। कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बारूदी सुरंगों और आईईडी विस्फोटों का शिकार होकर अपने अंग गंवाये वाले हर नागरिक को पुनः संबल देकर अपने पैरों पर खड़ा करना ही नक्सलवाद की अंतिम निशानी को मिटाना है। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि नक्सलियों ने भले ही धमाकों से लोगों के पैर छीने हों, लेकिन बस्तर की जनता के आत्मबल और मां दैतेश्वरी की कृपा से आज वही लोग कृत्रिम अंगों के सहारे स्वाभिमान से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री

ने आईईडी ब्लास्ट के शिकार ग्रामीण संतोष पोयाम सहित कर्तव्य के दौरान घायल हुए पुलिस जवान राकेश कुमार यादव और घासीराम मांझी की जीवत्ता का विशेष उल्लेख किया, जो अब कृत्रिम अंगों की मदद से बिना किसी सहारे के चलने के लिए तैयार हैं। यह पुनीत अभियान जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से रजयपुर फुटव् के लिए विख्यात भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एनएसई फाउंडेशन और भारतीय जैन संघटना के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है। शिविर की खासियत यह है कि यहां ऑन-साइट आधुनिक कार्याशला में विशेषज्ञों द्वारा दिव्यांगजनों का व्यक्तिगत नाप लेकर मौके पर ही आधुनिक कृत्रिम हाथ, पैर, कैलिपर्स तैयार कर लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले ही दित 70 से अधिक हितग्राहियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही जरूरतमंदों को न्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स, बैसाखी और श्रवण यंत्र पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम शिविर स्थल पर ही परीक्षण कर दिव्यांगजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट सौंप रही है और हितग्राहियों को मौके पर ही शत-प्रतिशत दिव्यांग पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में दम्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस महाशिविर के व्यापक विस्तार की जानकारी देते हुए भारतीय जैन संघटना के डॉ. अतुल जैन ने बताया कि पूर्व में यह शिविर कवर्धा के लिए प्रस्तावित था।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर सहज संवाद में जानी पढ़ाई और स्कूल की जरूरतें



से पढ़ाई, तिमाही परीक्षा की तैयारी, स्कूल की गतिविधियों और खेल-कूद के बारे में जानकारी ली। आत्मीय संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में प्रार्थना शेड एवं मंच निर्माण की आवश्यकता बताई। बच्चों की मांग पर मंत्री श्री यादव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रार्थना शेड एवं मंच निर्माण के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री श्री यादव ने विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीक का है।

विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ तकनीकी ज्ञान में भी दक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुगल, एक्सेल सहित विभिन्न संस्थाओं एवं कंपनियों के सहयोग से बच्चों को एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश लर्निंग कोर्स शुरू करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय, सेलुद पहुंचे और विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

करीब तीन साल बाद घरेलू सर्किट में लौटंगी मनिका बत्रा

■ पंचकुला। भारतीय टेबल टेनिस की शीर्ष महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा करीब तीन साल बाद घरेलू सर्किट में वापसी करेंगी।।मंगलवार से ताऊ देवी दाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही दूसरी शानल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वह पीएसपीबी का प्रतिनिधित्व करेंगी।मनिका ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में पंचकुला में सिनियर नेशनल्स में हिस्सा लिया था।। तब महिला एकल के दूसरे दौर में उन्हें हरिप्रणा की गैरवर्धेयपुथोकी की चक्रवर्ती ने 3-2 से हराया था।

गावस्कर की ये उम्मीद पूरी कर पायेंगे रोहित ?

मुम्बई। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर चाहते हैं कि भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लें, तब उनके एकदिवसीय शतकों की संख्या उनकी उम्र से कहीं अधिक हो। रोहित अगले साल होने वाले विश्व कप के दौरान 40 साल के हो जाएंगे। अभी उनके नाम डक्कक्रिकेट में 35 शतक हैं। गावस्कर को इसी कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय में रोहित के 92 रनों पर आउट होने का काफी दुख हुआ क्योंकि वह शतक पूरा नहीं कर सके। गावस्कर ने कहा कि अगर रोहित उस मुकामले में शतक लगाते, तो वह अपने 36वें एकदिवसीय शतक तक पहुंच जाते और इस खास उपलब्धि की दिशा में एक और कदम बढ़ाते। उनके मुताबिक, संन्यास के समय खिलाड़ी के शतकों की संख्या उसकी उम्र से ज्यादा होना एक बेहद खास उपलब्धि है, जो लंबी अवधि की निरंतरता और उच्च-स्तरीय प्रदर्शन को दर्शाती है. गावस्कर ने अपने करियर का उदाहरण भी दिया. उन्होंने बताया कि जब वह अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी दौर में थे, तब उनकी भी इच्छा थी कि टेस्ट क्रिकेट में उनके शतकों की संख्या उनकी उम्र के बराबर हो पर वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अपने करियर के आखिरी साल में वह तीन बार नर्वस नाइटिज में आउट हुए। वहीं अगर वह उन तीन पाठियों में शतक पूरा कर लेते, तो 38 साल की उम्र में संन्यास लेते समय उनके नाम भी 38 टेस्ट शतक होते.

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है अभी टीम में सभी खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में उभरते हुए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को टीम में अपने अवसर के लिए संयम से इंतजार करना पड़ता है। गंभीर ने कहा कि उन्होंने 15 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को समझाया है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद कभी-कभी खिलाड़ी को अपने अवसर के लिए संयम से इंतजार करना पड़ता है। गंभीर का यह बयान ऐसे समय आया है जब वैभव को हाल में घरेलू क्रिकेट में

वैभव को अभी इंतजार करना होगा: गंभीर

काफी रन बनाने के बाद भी टीम में जगह नहीं मिल रही है।

इसी साल जुलाई में, वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करते हुए 15 साल और 99 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय का खिताब अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। इसके तुरंत बाद, जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल और 118 दिन की उम्र में उन्होंने पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले



सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर एक और कीर्तिमान स्थापित किया। हालांकि, इन शानदार प्रदर्शनों के बावजूद, उन्हें अफगानिस्तान के

श्रीलंका के खिलाफ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में भारत की अंतिम ग्यारह में वापसी की, जहां उन्होंने 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर मैच में अहम भूमिका निभाई थी।

गंभीर ने कहा, यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था।हां, वह अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है। गंभीर ने इस बात पर जोर दिया कि प्लेइंग इलेवन का चयन सोशल मीडिया या बाहरी चर्चाओं से तय नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह पूरी

खिलाफ पूरी सीरीज और एशियाई खेलों से पहले जापान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी जगह नहीं मिली। वैभव ने



भी शामिल है। वह वर्तमान में श्रीलंका के मेजर वल्व्स लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में 63.85 के उत्कृष्ट औसत से 447 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर हैं। अदिका अपनी बाउंड्री लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं

तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम का समीकरण कैसा है, कौन सा खिलाड़ी कोच और कप्तान को मैच जिताने की क्षमता रखता है, तथा टीम की सबसे मजबूत अंतिम ग्यार ह क्या है। इसके साथ ही, उन खिलाड़ियों की निरंतरता भी महत्वपूर्ण होती है जिन्होंने लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारतीय मुख्य कोच ने आगे स्पष्ट किया कि टीम संयोजन में अचानक बदलाव क्यों नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा, अगर आज हम वैभव को मौका देते हैं, तो मेरे और टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ी- चाहे वह अभिषेक हों या संजु सैमसन के बीच

त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम में फर्नांडो, अराचिगे की वापसी

और कामिल मिशारा जैसे अन्य मजबूत टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जो टीम प्रबंधन के लिए एक दिलचस्प चुनौती होगी।

वहीं गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो, श्रीलंका ने इस त्रिकोणीय सीरीज के लिए चार प्रमुख तेज गेंदबाजों झ दूम्भशा चमीरा, असीथा फर्नांडो, इशान मलिंगा और दिलशान मधुशंका झ पर अपना भरोसा बनाए रखा है। स्पिन विभाग में, महेश थीक्षणा, सविंदु कोलंबेज और दुनिथ वेल्लालागे आक्रमण की कमान संभालेंगे, जो विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ यह महत्वपूर्ण त्रिकोणीय सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी। श्रीलंका अपना अभियान

रावलपींडी में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में करेगा, जहां वे जीत के साथ शुरुआत करने का लक्ष्य रखेंगे। यह सीरीज टीम के लिए आगामी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से पहले अपनी तैयारियों का आकलन करने का एक बेहतरतीन अवसर होगी। इसी को देखते हुए टीम ने टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों को भी तेज कर दिया है। त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम- पाथुम निसंका, अदिका फर्नांडो, कामिल मिशारा, कुसल मंडिस (कप्तान, विकेटकीपर), पावन रत्नरायके, सहान अराचिगे, कमिंदु मंडिस, जनिथ लियांगगे, दासुन शनाका, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षणा, सविंदु कोलंबेज, दूम्भशा चमीरा, असीथा फर्नांडो, दिलशान मधुशंका, इशान मलिंगा।

टीम इंडिया में वापसी के प्रयास कर रहे आकाशदीप और मुकेश कुमार

मुम्बई। युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप के साथ ही तेज गेंदबाज मुकेश कुमार एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी करना चाहते हैं। इन दोनों ही गेंदबाजों ने अपने डेब्यू के बाद से ही सभी को प्रभावित किया था पर चोटिल होने के कारण ये टीम में अपनी जगह बनाये नहीं रख पाये। ऐसे में अब ये दोनों चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में वापसी की राह देख रहे हैं।हाल ही में ईरानी टीम में रेंसर ऑफ इंडिया की ओर से खेले हुए रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मु-कश्मीर टीम के खिलाफ इन दोनों ने बेहतरीन खेल दिखाकर अपनी वापसी की दावेदारी की थी। आकाशदीप ने छह जबकि मुकेश कुमार ने दोनों पाठियों में कुल आठ विकेट लिए थे। वहीं जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाजों के पास इन दोनों की खिंग का कोई जवाब नहीं था। इन दोनों ने ही अपने प्रदर्शन से दिखाया है कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मुकामला इन दोनों के लिए महज एक ट्रॉफी जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। मुकेश जुलाई 2024 के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं और ऐसे में अपने को टीम से बाहर किए जाने के फ़ैसले को गलत साबित करने में जुटे हैं। वहीं, आकाशदीप कमर के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरने के बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे, जो लगभग आठ महीनों में उनका पहला मुकामला था। खास बात यह रही कि दो राष्ट्रीय चयनकर्ता मैदान के किनारे से उन पर बारीकी से नजर रख रहे थे, जो उनकी वापसी की संभावनाओं को बल देता है।

ब्रेसवेल ने लीग क्रिकेट खेलने लिया कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने साल 2026-27 सीजन के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (केंद्रीय अनुबंध) की जगह पर कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट (संविदात्मक) अनुबंध किया है। इससे ब्रेसवेल ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) सहित दुनिया भर की अन्य टी20 लीगों में में भी खेल सकेंगे। ब्रेसवेल के इस फैसले से घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली को पहली बार केंद्रीय अनुबंध मिला गया है। है। यह केली के करियर की एक बड़ी उपलब्धि है, जो उन्हें अपने

फस्ट-क्लास डेब्यू के लगभग 11 साल बाद मिली है। वहीं ब्रेसवेल अब उन खिलाड़ियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए भी पेशेवर क्रिकेट खेलने की राह बनायी है।वहीं फिन एलन, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ी पहले से ही संविदात्मक अनुबंध पर हैं। ब्रेसवेल ने स्पष्ट किया है कि भले ही उन्हें टी20 लीग में खेलने का अवसर मिलेगा, उनकी प्राथमिक प्राथमिकता अभी भी न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है। उन्होंने न्यूजीलैंड



क्रिकेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड ने उनके फैसले का समर्थन किया है। ब्रेसवेल, जो केवल संफेद गेंद क्रिकेट खेलते हैं,

ने इस बात पर जोर दिया कि उनके करियर के इस चरण में बिग बैश में खेलने का अवसर छोड़ना सही नहीं होगा। उन्होंने इस महीने के अंत में

कारोबार

मजबूत घरेलू मांग से भारतीय सेवा क्षेत्र में उछाल, तीन महीने के उच्चतम स्तर पर वृद्धि

नई दिल्ली। भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि सितंबर में तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मजबूत घरेलू मांग और नए ऑर्डर में तेज वृद्धि ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक मासिक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अगस्त के 54.1 से बढ़कर सितंबर में 55.2 हो गया। यह जुन के बाद से सबसे मजबूत वृद्धि का संकेत है।

परसेजिंग मेनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) में 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन बताता है। हालांकि, सेवा क्षेत्र की गतिविधि में यह वृद्धि पिछली तिमाही के औसत से ऊपर नहीं जा पाई। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी वित्तीय तिमाही में वृद्धि मार्च 2022 के बाद सबसे कमजोर रही।एसएंडपी ग्लोबल लगभग 400 सेवा क्षेत्र की कंपनियों से मिले जवाबों से एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई संकलित करता है।सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय सेवा क्षेत्र में वृद्धि कई कारकों से प्रेरित थी। इसमें डिजिटल समाधान, भोजन, बीमा, ऋण, सॉफ्टवेयर, परिवहन और पर्यटन की बढ़ी हुई मांग शामिल है। भारतीय सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में भी सुधार देखा गया। पैनलिरिस्टों ने जर्मनी, यूएसई, यूके और यूएस से लाभ की सूचना दी।एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने बताया कि भारतीय सेवा क्षेत्र में सुधार जारी रहा। यह मजबूत घरेलू मांग से समर्थित था। निर्यात कारोबार भी लगातार बढ़ा, हालांकि उसकी गति धीमी रही। सुघरते ऑर्डर और पाइपलाइन में मौजूद परियोजनाओं ने सेवा प्रदाताओं को सितंबर के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित किया। हालांकि, रोगाणु की दर अगस्त से कम रही। दूसरी वित्तीय तिमाही के अंत में लागत का दबाव कम हुआ।इनपुट मूल्य मुद्रास्फीति की दर नवंबर 2025 के बाद सबसे कमजोर स्तर पर आ गई। भंडारी ने कहा कि सेवा प्रदाताओं पर इनपुट लागत का दबाव 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया।इससे बिक्री मूल्य बढ़ाने का अवसरकता कम हुई।

निर्माण सामग्री ढोने वाले 80 फीसदी ट्रकों में नहीं लगा जीपीएस, सरकार ने फिर बढ़ाई समय सीमा

चेन्नई। तमिलनाडु में निर्माण खनिजों के परिवहन के लिए पंजीकृत पांच में से लगभग चार ट्रकों में जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण नहीं लगे हैं, जिसके चलते खनिज आवागमन की निगरानी को कड़ा करने के उद्देश्य से मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद स्थापना की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.

पोर्टल पर दर्ज वाहनों की वास्तविक स्थिति

खनिज प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर पंजीकृत 1.4 लाख ट्रकों में से 30 सितंबर तक केवल 30,000 ट्रकों में ही वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण लगे हुए थे. शेष 79 प्रतिशत ट्रकों को एम-रेत और अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ढकने की

आवश्यकता का पालन करना बाकी है.

समय सीमा बढ़ाने का पुराना खिलसा

भूविज्ञान एवं खनन विभाग ने परिवहन संघों द्वारा अतिरिक्त समय की मांग के बाद, समय सीमा के बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है. मूल समय सीमा 31 मार्च को पहले ही बढ़ा दी गई थी जबकि सरकार ने अलग से घोषणा की थी कि जीपीएस उपकरण के बिना वाहनों को 1 सितंबर से खनिज पारगमन पास मिलना बंद हो जाएगा.

निगरानी प्रणाली और इसका बड़ा महत्व

वाहन ट्रैकिंग को खनिज प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का उद्देश्य ट्रकों द्वारा सामग्री लोड



करने के स्थान और उनकी आवाजाही को रिकॉर्ड करके खनिज परिवहन की निगरानी को मजबूत करना है. ऐसे रिकॉर्ड

अधिकारियों को अनधिकृत खदानों से आने वाली आपूर्ति की पहचान करने और अवैध खनन और परिवहन उल्लंघनों की जांच

करने में मदद कर सकते हैं.

ट्रक संगठनों के आरोप और उपकरण की लागत

इस प्रणाली के धीमी गति से

विभाग की अपनी दलीलें और नई कार्रवाई

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लगभग 37 अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के पास अल्पावधि के भीतर शेष सभी वाहनों को सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त ट्रैकिंग नहीं है. एक अधिकारी ने बताया कि यह नवीनतम निस्तार कई संगठनों के अनुरोधों के बाद किया गया है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि फर्जी क्यूआर कोड वाले फर्जी खनिज पारगमन पास बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. खनन संबंधी उल्लंघनों की शिकायतों के लिए जल्द ही एक सर्मापित नंबर शुरू किया जाएगा और इसे चेन्नई स्थित विभाग के नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा.

लागू होने पर ट्रक मालिकों ने सरकार की इस प्रणाली को लागू करने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं. तमिलनाडु राज्य ट्रक मालिक संघ के महासचिव जी. गणेश ने कहा कि ट्रैकिंग उपकरणों की लागत में भारी गिरावट आई है, जो 15,000 रुपये से घटकर 3,700 रुपये हो गई है.

जी. गणेश ने कहा कि कई विक्रेता एआईएस-140 मानक को पूरा करने वाले एक लाख से

अधिक उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं और उनका तर्क था कि उपलब्धता को देखते हुए और देरी को उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस आवश्यकता को लागू करने में सरकार की अनिच्छा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उसके संकल्प पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मांग और आपूर्ति का बड़ा अंतर

निर्माण की मांग और अधिकृत खदान उत्पादन के बीच पर्याप्त अंतर के बीच प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं. तमिलनाडु में निर्माण सामग्री की औसत दैनिक आवश्यकता लगभग 5.25 लाख यूनिट है, जबकि खदानों से अनुमत उत्पादन केवल 1.2 लाख यूनिट है, जो गहन नियामकीयजांचकी आवश्यकता को उजागर करता है.

